डिजिटल डेमोक्रेसी से बदलती दुनिया

सफलता की चुनिंदा कहानियां

VIKAS SAMVAD

किताब का नाम : **डिजिटल डेमोक्रेसी से बदलती दुनिया**

सहयोगी : सचिन कुमार जैन, राकेश कुमार मालवीय, अरविंद मिश्र, दीपक मिस्त्री, वरुण नामदेव, गगन नायर, सीमा प्रकाश, निलेश देसाई, युसुफ बेग, विनोद गुप्ता, राजीव भार्गव, रामकुमार विद्यार्थी, सचिन श्रीवास्तव, गुरुशरण सचदेवा, चिन्मय मिश्र, अनिल चौधरी।

पृथ्वी ट्रस्ट–पन्ना, संपर्क समाजसेवी संस्था–झाबुआ, निवसीड बचपन–भोपाल और स्पंदन–खंडवा के सभी साथी, ई–वालंटियर और विकास संवाद के सभी सहयोगी।

प्रकाशक : विकास संवाद
ई–7/226, प्रथम तल, धनवंतरी कॉम्प्लेक्स के सामने
अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश
vikassamvad@gmail.com
www.mediaforrights.org / www.vssmp.org
(0755-4252789)

प्रतियां : 500

वर्ष : 2019

डिजाइन : अमित सक्सेना

मुद्रक : स्पेसिफिक प्रिंटर्स

वित्तीय सहयोग : फोर्ड फाउंडेशन

भूमिका

डिजिटल डेमोक्रेसी के पहले अध्ययन में हमने समझा था कि इंटरनेट बड़ी ताकत है, लेकिन तकनीकी ज्ञान और सर्वसुलभता के अभाव में एक बड़ा अंतर है। एक डिजिटल डिवाइड है। इस डिवाइड को खत्म करने के लिए सरकार ने पुरजोर कोशिश की है, एक छोटी सी कोशिश हमने भी की। चार जिलों की पंचायतें और हमारे सौ ई-वालंटियर साथी। एक मोबाइल फोन और इंटरनेट का सदुपयोग। अपने आसपास की समस्याएं और वंचित, पीड़ितों के लिए संवेदना।

पिछले दो-ढाई सालों की इस पहल का कुल जमा यही तो यही है, लेकिन इसने संभावनाओं के लिए नए रास्ते बना दिए हैं। लोकतंत्र और मुखर हुआ है इस इंटरनेट के जरिए। इस किताब में दी गई इन छोटी-छोटी कहानियों के जरिए आप जान पाएंगे कि किस-किस तरह लोगों ने इंटरनेट को अपने हाथ में लिया और अपने गांव के लिए, अपने समुदाय के लिए, खेती-किसानी के लिए, पेंशन के लिए, रोजगार के लिए, घर को सुंदर बनाने के लिए, हैंडपंप ठीक करवाने के लिए, बिजली लाने के लिए, पढ़ाई के लिए, सोती व्यवस्था को जगाने के लिए किया। इसमें परेशानियां भी आईं, थोड़ी तकरार भी हुई, लेकिन इस तकरार के पीछे भी मकसद रहा लोगों को उनके वाजिब हकों को दिलाने का।

इस किताब को छापने का मकसद सिर्फ इतना है कि इनके जरिए आप डिजिटल डेमोक्रेसी के इस मॉडल को समझ पाएं। यह निश्चित तौर पर कोई बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन एक मॉडल स्थापित करने के नजरिए से हमें यह कहानियां तसल्ली देती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनेट की इस ताकत को सकारात्मकता के साथ भी समझा जाए और इसका उपयोग डिजिटल डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए किया जा सके।

अनुक्रमणिका

बिजली नहीं थी तो लड़की वाले मुड़कर नहीं देखते थे	3
डिजिटल माध्यम की ताकत से मिल गई छत	6
ट्वीट किया तो सुधरी सड़क, मिली बिजली	7
अमसिया ने डिजिटल प्लेटफार्म से बदल ली ख़ुद की ज़िंदगी	11
चार युवाओं ने शुरु किया अपना काम, मिली पलायन से मुक्ति	13
ऑनलाइन वीडियो देखकर बदल दी किसानों की तकदीर	15
गायत्री ने ऑनलाइन बनाया इनोवेटिव लैंप	17
सामाजिक मुद्दों और समस्याओं पर एक माह में शेयर किए 58 वीडियो	18
ट्वीट से आई बिजली और मिली साइकिल तो खुली स्कूल की राह	21
खुद का काम शुरु किया तो बच्चों की शिक्षा में आया सुधार	24
अतरवती बनीं महिलाओं की हमदर्द	26
यू-ट्यूब से समझे बीमारी से बचाव के उपाय	29
पूजा ने पाई अनजान नंबर से कॉल और मैसेज से मुक्ति	31
ई-दस्तक केंद्र ने दिलाया पूरा राशन	34
ई-दस्तक केंद्र ने दिलाई खुशी, दिलाया छिना हुआ निवाला	36
ऑनलाइन शिकायत के बाद मिली पात्रता पर्ची	38
शिकायत के बाद दोबारा नहीं दिया गया एक्सपायर्ड पोषाहार	41
दशरथ ने सीएम हेल्पलाइन पर की शिकायत तब सुधरा हैंडपंप	43
ऑनलाइन शिकायत से डरे सचिव, गंगा को दिलाई पेंशन	46
पांच साल से अंधेरे में था गांव, बिच्छू ने छीन ली थी मासूम की जिंदगी	48
ई-दस्तक केंद्र ने साफ किया बुजुर्ग की पेंशन का रास्ता	51
पूनम ने यू-ट्यूब देखकर शुरू किया स्टार्टअप	53
भुलिया से छिना जीने का सहारा तो काम आया डिजिटल प्लेटफार्म	55
यू-ट्यूब लाया संध्या के जीवन में नया सवेरा	57
फिंगर प्रिंट नहीं आए तो भोजन का अधिकार से वंचित हुए दो परिवार	60
सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की तब सुधरे हैंडपंप	63
ई-वालंटियर की मदद से मिला भोजन का अधिकार	66
डिजिटल डेमोक्रेसी से जागी उम्मीदें, मिली मदद	68
ई-दस्तक केंद्र ने लौटाई फुंदा और धना की खुशी	70
चार अनाथ बच्चों को मिला जीने का सहारा	72
ऑनलाइन शिकायत की तो मिली कुएं की राशि	75
स्कूल के लिए अब हथेली पर नहीं होगी जान	77

बिजली नहीं थी तो लड़की वाले मुड़कर नहीं देखते थे

लड़का कमाता नहीं हो या चाल–चलन ठीक न हो तो शादी के लिए लड़की नहीं मिलने के किस्से आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन पन्ना जिले के आदिवासी गांव राजापुर (रमखिरिया) का मामला जरा हटकर था। पन्ना और राजापुर की दूरी महज 37 किलोमीटर है। इसके बावजूद मूलभूत सुविधाओं को लेकर भारी अंतर है। अमूमन माता–पिता को बेटी के हाथ पीले करने की चिंता सताती है, लेकिन राजापुर के लोगों को बेटे के लिए बहू लाने की चिंता खाए जाती थी। लड़की वाले आते। रातभर रुकते और वापस जाते तो मुड़कर दोबारा नहीं देखते। जिनके यहां शादियां हुईं, वो बड़ी मुश्किलों से हुईं। राजापुर की गलियों में जाकर पता किया लोगों के बीच बैठकर उन्हें कुरेदा तो और भी कई समस्याएं खुलकर मालूम पड़ीं। इन तमाम समस्याओं की जड़ एक ही थी। राजापुर में बिजली का न होना। रात के अंधेरे ने कई परिवारों की आस को अंधकार में डुबो रखा था। हालांकि, अब वहां बिजली भी है और लोगों की घर में बहू लाने की इच्छा भी पूरी हो रही है। इसका हल ढूंढा यहीं के 63 वर्षीय हल्के खैरवार ने। यहां अकेले रहने वाले हल्के की तमाम कोशिशों और समझ की चर्चा भी करेंगे। बहरहाल, राजापुर की समस्याओं पर बात करते हैं।

राजापुर की समस्याओं की फेहरिस्त लंबी है। बकौल, हल्के खैरवार करीब 80 आदिवासी परिवार वाले इस गांव में रात होते ही मजबूरन सभी अपने घरों में कैद हो जाते थे। रात का भोजन शाम पांच बजे तैयार हो जाता और सूर्यास्त तक खाकर सभी सो जाते। अंधेरे में जहरीले जीव–जंतुओं के काटने का खौफ बना रहता। बिच्छू के डंक मारने की कई घटनाएं हो चुकी थीं। रोशनी के लिए चिमनी और लालटेन थीं, लेकिन केरोसिन इतना नहीं

मिल पाता था कि इनसे घर देर तक रोशन करें तो केरोसिन महीनेभर चल जाए। चंदू गोंड और भूरा गोंड भी कुछ इसी तरह की समस्याएं बताते हैं। बिजली नहीं होने का एक कारण गांव के लोगों की जिले तक पहुंच कम होना और सतत संपर्क नहीं हो पाना भी था। कभी किसी ने शिकायत की भी तो सिस्टम के कान में जूं नहीं रेंगी। वह अपने ढर्रे पर काम करता रहा। एक बिजली नहीं होने से ये आदिवासी परिवार बाहरी दुनिया और सूचनाओं से लगभग कटे हुए थे। बच्चे पढ़ नहीं पाए, इसलिए पूरा गांव शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इनकी आय का मुख्य स्रोत आज भी महुआ, अचार, तेंदूपत्ता, आंवला आदि वनोपज हैं। बाकी समय हीरा खदानों में 120 रुपए रोज मजदूरी करते हैं। इस परिवेश में जीवन बसर कर रहे इन आदिवासियों से अपना काम कराने के लिए सरकारी सिस्टम पर दबाव बनाने की उम्मीद करना बिना आधुनिक तकनीक के संभव नहीं था। जरूरत थी, इस सिस्टम से सतत संपर्क की। उस पर दबाव बनाने की। चूंकि, हल्के खैरवार यहां परचूनी की दुकान चलाते हैं, इसलिए वे हर सोमवार को सामान खरीदने के लिए अपने गांव से करीब छह किलोमीटर दूर बृजपुर जाते हैं। यहां हर सोमवार को बाजार लगता है।

बृजपुर की बात करें तो राजापुर की अपेक्षा कुछ ठीक स्थिति में है। यहां के लोग राजापुर की जैसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए नहीं कहे जा सकते। यहां ई–दस्तक केंद्र है, जहां से इंटरनेट से जुड़ी जानकारी उनको मिलती है। इंटरनेट से जुड़े उनके कई काम हो जाते हैं। डिजिटल तकनीक की खूबियां उनको बताई जाती हैं। करीब डेढ़ साल पहले हल्के हर बार की तरह सामान लेने बृजपुर गए, जहां कुछ परचे बांटे जा रहे थे। ये ई–दस्तक केंद्र था। एक परचा हल्के को भी मिला। हल्के कहते हैं – मैंने यह परचा पढ़ा। कुछ बातें समझ आईं तो कुछ बातें पल्ले नहीं पड़ीं। इतना जरूर समझ आया कि यहां समस्याओं के समाधान का रास्ता निकल सकता है। मैंने अपने गांव में बिजली नहीं होने की समस्या बता दी। तब, परचा बांटने वालों ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर फोन करके अपनी समस्या बताने की सलाह दी। गांव में बिजली लाने का असल और सतत संघर्ष यहीं से शुरू हुआ।

अब हल्के के लिए बिजली से पहले मोबाइल फोन होना जरूरी था, जिसे चार्ज करने के लिए भी उन्हें करीब तीन किलोमीटर दूर रमखिरिया जाना पड़ता। इसके बावजूद वे हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने 600 रुपए में एक पुराना मोबाइल फोन खरीदा और 181 पर कॉल करके अपने गांव राजापुर में बिजली नहीं होने की शिकायत दर्ज करवा दी। ये पूरी व्यवस्था जुटाने और फोन करने में उन्हें एक सप्ताह का समय लगा। इसके बाद बिजली महकमे में दबाव बनना शुरू हुआ। अब जैसा कि हल्के को बताया गया था, उस हिसाब से वे अपनी शिकायत की जानकारी लेते रहे। इसके लिए उन्हें फोन करना पड़ता था। और, मोबाइल चार्ज करने के लिए वहीं रमखिरिया तक जाने–आने के छह किलोमीटर का सफर करना पड़ता। फिर भी हल्के अपनी जिद पर अड़े रहे। इससे अफसर–कर्मचारियों पर दबाव बढ़ा, जिसका असर ये हुआ कि शिकायत दर्ज कराने के करीब एक माह बाद राजापुर में बिजली पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते करीब दो माह के भीतर पूरा गांव बिजली से जगमगा उठा। अब गांव में रात में भी कुछ चहल–पहल रहती है। लोग शाम होते ही घरों में कैद नहीं

होते। जहरीले जीव–जंतुओं के काटने का खौफ पहले जितना नहीं रहा। गांव में टीवी पहुंचा, जिससे ये आदिवासी परिवार मनोरंजन के साथ ही दुनियाभर की खबरों से रूबरू हो रहे हैं। उनके परिवारों में युवकों की शादियां भी होने लगी हैं। हल्के ने बताया कि ई–दस्तक केंद्र से उन्हें डॉयल 100 और 108 के बारे में भी जानकारी दी गई। इससे गांव के सभी लोगों को मदद मिली। हल्के का आत्मविश्वास और संघर्ष देखकर गांव के अन्य लोग भी उनसे जुड़ गए। इसके बाद हल्के ने पेयजल समस्या के समाधान के लिए गांव के चार लोगों की ड्यूटी लगा दी कि वे 181 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं और उसे फॉलो करते रहें।

चंदू गोंड ने बताया कि अब गांव के 70 प्रतिशत घरों में मोबाइल फोन है। वे बाहरी दुनिया से जुड़ चुके हैं। अपने रिश्तेदारों से बात कर पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे बच्चे अब पढ़–लिख रहे हैं। इससे उनका भविष्य संवर सकता है। हालांकि, चंदू यह भी कहते हैं कि उनके गांव के लोग डिजिटल तकनीक की और बारीकियां सीखें। वहीं, राजापुर के ही भूरा गोंड ने कहा कि समय के साथ चलना है तो इंटरनेट की दुनिया से जुड़ना जरूरी है। इसके जरिए तमाम सरकारी योजनाओं और नौकरियों की जानकारी मिल सकती है। समग्र आईडी, आधार कार्ड सहित कई काम ऐसे हैं, जिनके लिए डिजिटल माध्यम की जरूरत पड़ती है। भूरा कहते हैं ये काम ई–दस्तक केंद्र और स्मार्टफोन के जरिए भी किए जा सकते हैं। वे कहते हैं कि गांव के लोगों के पास जब तक स्थायी रोजगार होना भी जरूरी है।

हल्के के संघर्ष और उनके गांव राजापुर की कहानी पता करना इतना आसान नहीं रहा। दरअसल, ई–दस्तक केंद्र बृजपुर से राजापुर का यूं सीधा संबंध नहीं है। यहां से तो सैकड़ों लोगों को डिजिटल डेमोक्रेसी की जानकारी दी जाती है। हल्के और राजापुर की कहानी रमखिरिया से पता चली। रमखिरिया ग्राम पंचायत का सर्वे किया गया। यहां के गांव कुंवरपुर में चर्चा के दौरान सूरजदीन गोंड ने बताया कि पास के गांव में हल्के खैरवार ने किस तरह अपने गांव को बिजली से रोशन कराया। इसके बाद राजापुर जाकर हल्के से बात की।

गांव में नई रोशनी खिल रही है।

डिजिटल माध्यम की ताकत से मिल गई छत

केस - 1

खंडवा जिले के डाभिया गांव में रहने वाले 50 वर्षीय कलीराम मजदूर हैं। एक दिन पंचायत सचिव अजय चावडा और सरपंच कपिल दिनकर ने उनसे कहा– तुम्हारे नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मंजूर हुआ है। पुराना मकान तोडकर नया बनाने की तैयारी करो। कलीराम ने उनकी बातों में आकर अपना मकान तोड़ लिया। कलीराम पीएम आवास का पैसा लेने बैंक गए तो जवाब मिला कि उनके खाते में रुपए नहीं हैं। यह सुनते ही उनके होश उड़ गए। उनका छह सदस्यीय परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया।

केस - 2

डाभिया गांव के ही 45 वर्षीय मनोहारी झानू से पंचायत सचिव अजय चावडा और सरपंच कपिल दिनकर ने कहा कि अपना मकान तोड़कर नया मकान बनाने के लिए गड्ढे खोद लें। उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा मंजूर हुआ है। खुशी के मारे मनोहारी ने अपना मकान तोड़ा और नए मकान के लिए गड्ढे खोद लिया। घर बनने तक अपने पांच सदस्यीय परिवार के रहने के लिए एक झोपड़ी बना ली। मनोहारी पीएम आवास योजना का पैसा लेने बैंक गए तो उनके खाते में राशि नहीं आई थी। वे निराश होकर घर लौट आए।

प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता तय होने और पैसे मिलने की लेटलतीफी के ऐसे कई मामले सामने आते हैं। समय पर किस्त नहीं मिलने से हजारों परिवार छप्परों में रहने को मजबूर हैं। दरअसल, इनके पास इतनी राशि भी नहीं होती है कि अपना मकान खुद बना सकें। इनकी ये दुर्दशा सरकारी सिस्टम की उदासीनता का परिणाम होती है। वे पुराना मकान पंचायत सचिव अजय चावडा और सरपंच कपिल दिनकर के आश्वासन पर तोड़ ही चुके होते हैं और नए के बनने का ठिकाना नहीं रह जाता, लेकिन खंडवा से 60 किलोमीटर दूरस्थ डाभिया गांव के कलीराम और मनोहारी ने इस सिस्टम को भी सबक सिखा दिया। उन्होंने जिद पकड़ी और अपनी लड़ाई खुद लड़ी। बीपीएल कार्ड धारी कलीराम महज दो एकड़ खेती में बोवनी के बाद दूसरी जगह मजदूरी करते हैं। यही हाल तीन एकड़ के कास्तकार मनोहारी का है। अंततः प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें उन्हें मिली और मकान भी तैयार हो गया। इस काम में डिजिटल डेमोक्रेसी का ई–दस्तक केंद्र उनके लिए मददगार साबित हुआ।

दरअसल, कलीराम और मनोहारी के मामले एक जैसे ही हैं। दोनों को सिस्टम ने झटका दिया तो काफी निराश हो गए। इन्हीं दिनों उन्हें डिजिटल डेमोक्रेसी कार्यक्रम की जानकारी मिली। उन्हें बताया गया कि यहां से कोई न कोई रास्ता निकल सकता है। वे उम्मीद लिए बैठक में पहुंचे और ई–दस्तक केंद्र की गतिविधियों को समझा। दोनों को कुछ भरोसा जगा तो ब्लॉक समन्वयक रामशंकर के सामने अपनी पीड़ा बयां कर दी। उन्होंने समाधान का रास्ता पूछा। इस पर रामशंकर ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। यहां से कलीराम और मनोहारी ने ठान लिया कि वे समस्या का समाधान कराकर रहेंगे। चूंकि, स्थानीय स्तर पर सरपंच और पंचायत सचिव से भी परिचय था, इसलिए उन्होंने एक बार सचिव से बात कर लेना बेहतर समझा। एक दिन कलीराम ने पंचायत सचिव को उनके आश्वासन के बाद बिगड़ी घर की स्थिति सहित तमाम बातें बता दीं। साथ ही यह भी कहा कि अब वे इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराएंगे। कलीराम की ये बात सुनकर सचिव के होश उड़ गए। उसने कलीराम से शिकायत नहीं करने की मिन्नतें की। करीब 15 दिन में पैसा आ जाने का आश्वासन दिया। इस पर कलीराम ने कुछ समय और इंतजार किया। इस बीच इसी सिलसिले में पांच–छह बार पटाजन भी गए, लेकिन काम नहीं हुआ।

कलीराम ने अपने तमाम प्रयास और सचिव से हुई बातचीत की जानकारी डिजिटल डेमोक्रेसी की कार्यकर्ता बबीता को दी। इस पर सचिव से दोबारा कहा गया कि वे यह मामला सीएम हेल्पलाइन में ले जाएंगे। वहां कॉल करके शिकायत दर्ज कर रहे हैं। सचिव ने इस बार आठ दिन में पैसा आ जाने का आश्वासन दिया, इससे लगा कि उस पर दबाव बन रहा है। वहीं, रामशंकर ने एक और चेतावनी दी कि आठ दिन में पैसा नहीं आया तो वे इस मामले की शिकायत कलेक्टर की जनसुनवाई में भी करेंगे। पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस गड़बड़ी की जानकारी पहुंच सके। इसके बाद सचिव के चेहरे की रंगत उड़ गई। इस घटना के करीब आठ दिन बाद कलीराम ने अपना बैंक खाता चौक कराया तो उसमें पीएम आवास के पैसे आ चुके थे। हालांकि,

इस योजना के तहत मजदूरी के 18000 रुपए उन्हें नहीं मिले थे, जिसके लिए उन्हें दोबारा शिकायत करना पड़ा। इस तरह कलीराम का काम तो ऑनलाइन शिकायत की चेतावनी से ही हो गया।

वहीं, मनोहारी को एक गफलत के कारण पीएम आवास योजना का पैसा नहीं मिल रहा था। इस गफलत का खुलासा भी सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत करने के बाद हुआ। मनोहारी भी कलीराम की ही तरह अपना पुराना घर तोड़ चुके थे। खाते में पैसा नहीं आया था। मनोहारी ने रामशंकर की सलाह के बाद सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई तो उनको पैसा नहीं मिलने की पड़ताल शुरू हुई। इसमें सरकारी सिस्टम की बड़ी गड़बड़ सामने आई कि मनोहारी का पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा कर दिया गया था। दरअसल, मनोहारी का खाता नंबर ही सही दर्ज नहीं किया गया था। इसके बाद रामशंकर ने मनोहारी को सलाह दी कि पैसा उनके खाते में जब तक जमा नहीं हो जाता तब तक वे शांत नहीं बैठें। इसकी शिकायत कलेक्टर की जनसुनवाई में जाकर करें। मनोहारी ने इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर की जनसुनवाई में करने को तैयार हो गए। इसकी सूचना सचिव को भी दी। इसका असर ये हुआ कि सचिव ने मनोहारी को बुलाकर रेत, गिट्टी, सीमेंट, लोहा आदि निर्माण सामग्री खरीदकर दे दी। इसके बाद मनोहारी ने अपने घर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अब मनोहारी का घर पूरा बन चुका है।

मनोहारी और कलीराम कहते हैं कि डिजिटल माध्यम की ताकत से उनके परिवार को छत मुहैया हो सकी। वरना सरपंच और सचिव की गफलत में उनके परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए थे। दोनों ने यह भी बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद उनके गांव में सात अन्य लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है। अब वे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लचर सरकारी सिस्टम से लड़ने का हथियार मानने लगे हैं।

> “हम इस समस्या को लेकर सरपंच और पंचायत सचिव के पास कई बार गए, लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद संस्था के ई-दस्तक केंद्र पर डिजिटल प्लेटफार्म की जानकारी मिली। डिजिटल प्लेटफार्म की ताकत से परिवार को छत मुहैया हो सकी।”
>
> – शंकर

ट्वीट किया तो सुधरी सड़क, मिली बिजली

सड़क और बिजली बुनियादी जरूरतें हैं, लेकिन जिम्मेदारों की मनमानी के कारण कई बार लोग इनसे वंचित रह जाते हैं। वहीं, इनकी कागजी उपलब्धता के मामले भी सामने आते रहे हैं। इससे एक बड़ी आबादी परेशान होती रहती है। ग्रामीण शिकायत करें तो सिस्टम के कानों तक पहुंच नहीं पाती। ज्यादातर मामलों में सरकारी कार्यालयों के फेरे लगाना और निराश होकर लौट आना ही उनके हिस्से में रह जाता है। सड़क और बिजली के ऐसे दो मामले पन्ना जिले के हैं। यहां सड़क पर बड़े–बड़े गड्ढे हो चुके थे, जिनसे हादसे हो रहे थे। खंभे गाड़े गए थे, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई थी। ग्रामीणों ने डिजिटल तकनीक का सहारा लिया तो दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। इससे पहले वे जिम्मेदारों से शिकायत करते रहें, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया और न ही कोई सकारात्मक कदम उठाया।

गड्ढों के कारण हो रहे थे हादसे

पन्ना से पहाड़ीखेड़ा तक 40 किलोमीटर लंबी सड़क कई मायनों में अहम है। यह पन्ना को यूपी के ऐतिहासिक स्थल कालिंजर और चित्रकूट से जोड़ती है। इससे पन्ना जनपद पंचायत की 25 पंचायतों के करीब 50 गांवों की आबादी का सीधा सरोकार है। दरअसल, यह जिला पंचायत, जिला प्रशासन, हाट सहित अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए इकलौता सीधा रास्ता है। सड़क संकरी और वाहनों की आवाजाही अधिक होने के कारण परेशानी तो बनी रहती है, लेकिन बड़ी परेशानी तब खड़ी हुई जब पन्ना से करीब 23 किलोमीटर दूर सिरस्वाहा बांध के पास वाली बडगडी के ढाल पर बड़े–बड़े गड्ढे हो गए। यहां प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही थीं। लोग

घायल हो रहे थे। यह सिलसिला तीन माह से चल रहा था। 21 अक्टूबर 2018 को रेत का डंपर पलटकर नाले में गिरा, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई।

सड़क की दुर्दशा और हादसों की जानकारी बृजपुर पंचायत के धनौजा निवासी ई–वालेंटियर गणेश गोंड और कम्यूनिटी मोबेलाइजर रमेश गोंड को मिली तो उन्होंने इसके समाधान की राह निकाली। रमेश ने ई–प्लेटफार्म का सहारा लिया और 22 अक्टूबर को एक ट्वीट किया। इसमें सड़क के फोटो अटैच कर दिए। उन्होंने इस ट्वीट के जरिए पन्ना कलेक्टर को सड़क की दुर्दशा और हादसों की जानकारी दी। रमेश के ट्वीट पर गणेश ने रीट्वीट किया। इसके बाद मुहिम के साथी लगातार रीट्वीट करते रहे। अंततः करीब 15 दिन बाद तहसीलदार को मौका मुआयना करना पड़ा। तहसीलदार के निरीक्षण करने के बाद जेसीबी और मजदूरों की मदद से सड़क के गड्ढों को भरवा दिया गया। तीन माह पुरानी समस्या हल हुई तो लोगों ने शिकायतकर्ता के बारे में जानना चाहा। इस पर उन्हें बताया गया कि यह काम मोबाइल फोन के जरिए गणेश और रमेश ने किया है। इसके बाद गांव वालों को ई–प्लेटफार्म से समस्याओं का समाधान कराना आसान लगा।

ऐसे लगी स्ट्रीट लाइट

दूसरा मामला ग्राम धनौजा में स्ट्रीट लाइट का है। गांव में बिजली आ चुकी थी। लिहाजा सड़कों के किनारे खंभे थे, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई थी। ग्रामीण मौखिक शिकायत कई बार कर चुके थे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। उन्होंने सरपंच और सचिव से भी स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की। अंत में ई–वालेंटियर सुरेश गोंड ने ई–दस्तक केंद्र की सलाह पर ग्रामसभा में प्रस्ताव रखा। इस पर गांव वालों के हस्ताक्षर कराए। ग्रामसभा में कुल आठ प्रस्ताव आए। इनमें स्ट्रीट लाइट का प्रस्ताव भी शामिल था। इसे मंजूरी मिली और कुछ दिनों बाद गांव में स्ट्रीट लाइट लगा दी गई। अब शाम होते ही गांव की सड़कें बिजली की रोशनी से जगमगाती हैं। सुरेश ने बताया कि ई–दस्तक केंद्र पर जाने से पहले उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए शिकायत कहां करना चाहिए, इसलिए परेशान होते रहे। ई–दस्तक केंद्र ने सही राह बताई तो समस्या का समाधान हो गया।

> **“मैं और जितेंद्र गोंड इस रोड से रात आठ बजे पहाड़ीखेड़ा से अपने गांव धनौजा जा रहे थे। लेकिन, सड़क पर गड्ढों के कारण हमारी मोटरसाइकिल गिर गई। इससे मुझे सिर में गंभीर चोट आई। मुझे सात दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था।”**
>
> **– सुरेश गोंड**

अमसिया ने डिजिटल प्लेटफार्म से बदल ली ख़ुद की ज़िंदगी

भटिया टोला के लोग तड़के धुंधलके में जागते और जरूरी दैनिक कार्यों से निपटकर हीरा खदानों में मजदूरी के लिए निकल पड़ते। महिलाओं और युवतियों पर पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा जिम्मेदारियां रहती हैं क्योंकि उनके खाना बनाना, बर्तन साफ करना, बच्चों के लिए दिनभर की व्यवस्था करने जैसे काम भी रहते हैं, लेकिन मजदूरी के लिए उन्हें भी पुरुषों–युवकों और वृद्धों के साथ ही जाना पड़ता है। महिलाएं और युवतियां शाम को आकर फिर काम में जुट जाती हैं। इन्हीं में शामिल थीं आदिवासी लड़की अमसिया, जिसकी जिंदगी में डिजिटल प्लेटफार्म ने आमूलचूल बदलाव ला दिया। अब वह मजदूरी नहीं करती। अमसिया की खुद की दुकान है। वह अब दूसरे लोगों की मददगार बन गई है। जिस तरह अमसिया को मजदूरी से मुक्ति मिली, वह चाहती है कि दूसरी महिलाओं और युवतियों को भी इससे मुक्ति मिले। इसके लिए उन्हें घरेलू रोजगार और कौशल विकास के बारे में जानकारी देती है। भटिया टोला गांव पन्ना जिले की बृजपुर पंचायत में आता है। यहां करीब 50 आदिवासी परिवार कच्चे मकान और झोपडियों में रहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक भटिया टोला नहीं पहुंची है।

अमसिया
(ई–वालंटियर)

18 वर्षीय अमसिया ने 10वीं में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और हीरा खदानों में मजदूरी करने लगी। अमसिया का कहना है कि वो हर दिन एक

दोना चाली मचाती थीं। इसके बदले में उन्हें 120 रुपए मिलते थे। किसी दिन मजदूरी नहीं मिले उदास होकर लौट आती थी। सच पूछो तो अमसिया को हीरा खदानों में काम करना अच्छा नहीं लगता था। अमसिया के परिवार में माता–पिता और दो बड़े भाई है, लेकिन स्थायी रोजगार किसी के भी पास नहीं है। इसलिए, अमसिया को खदानों में मजदूरी के लिए जाना पड़ता था। वह इससे छुटकारा चाहती थी। वह खुद का काम शुरू करना चाहिए थी। इसकी राह अमसिया के भाई रमेश के मोबाइल फोन से निकल पड़ी, जिसके बाद डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना से मदद मिली और अमसिया आज अपनी मेहनत से 300 से 400 रुपए रोज की बचत कर रही है।

दरअसल, अमसिया मोबाइल में यू–ट्यूब पर खाना बनाने और स्व–रोजगार से जुड़े वीडियो देखा करती थी। एक दिन घर में पानी पुरी खाने का मन हुआ तो इसका वीडियो देखा। इसके बाद पानी पुरी बनाई तो घर में सभी को पसंद आई। सभी ने अमसिया की तारीफ की। इसके बाद अमसिया ने भटिया टोला में नवोदय विद्यालय के सामने पानी पुरी की दुकान खोलने का मन बनाया। अमसिया ने परिवार के सहयोग से एक झोपड़ी बनाई और पानी पुरी, समोसा आदि की दुकान खोल ली। करीब तीन–चार दिन बाद से 600–700 रुपए तक की बिक्री होने लगी, जिसमें करीब 300–400 रुपए की बचत हो जाती है। अब अमसिया ने दुकान में किराने का सामान भी रख लिया है। दुकान के कारण अमसिया को अन्य महिलाओं और युवतियों की मदद करने का समय भी मिल जाता है।

अमसिया ने बताया कि उनकी सफल कहानी में ई–दस्तक केंद्र की बड़ी भूमिका है। वह भटिया टोला में केंद्र की बैठक में शामिल हुई, जहां से डिजिटल प्लेटफार्म की तमाम जानकारियां मिलीं। ये जानकारी दूसरों तक पहुंचाने की मंशा से वह ई–वालेंटियर बन गई। अमसिया के भाई रमेश कम्युनिटी मोबलाइजर के रूप में काम करते हैं। उनके पूरे गांव में महज सात लोगों के पास स्मार्टफोन है। वह कौशल विकास की क्लास में लगातार शामिल हुई। अब वह गूगल पर सरकारी योजनाओं, शिक्षा आदि से जुड़ी जरूरी जानकारी सर्च कर लेती है। अमसिया के जीवन में आए बदलाव के बाद से गांव के लोग किसी भी सरकारी योजना की जानकारी के लिए ई–दस्तक केंद्र जाते हैं।

अब भविष्य का प्लान तैयार

अमसिया ने रोजगार का अपना साधन खड़ा करने के बाद आगे की पढ़ाई पूरी करने की ठानी है। इसी के साथ वह ई–दस्तक केंद्र और यू–ट्यूब के माध्यम से महिलाओं और युवतियों को घरेलू रोजगार से जोड़ना चाहती है, जिससे उन्हें हीरा खदानों में मजदूरी करने से मुक्ति मिल सके। वे आत्मसम्मान के साथ जी सकें। अमसिया ने बताया कि बस्ती की सुनीला, विद्दो बाई, मीराम, रामप्यारी, राजाबाई, कलाबाई सहित गांव के कई लोग उनसे ई–तकनीक की जानकारी लेने आते हैं।

चार युवाओं ने शुरु किया अपना काम, मिली पलायन से मुक्ति

झाबुआ जिले के पेटलावद ब्लॉक के चार युवाओं ने डिजिटल डेमोक्रेसी को ही आजीविका का साधन बना लिया। हम यहां पेटलावद से 28 किलोमीटर दूरस्थ ग्राम पंचायत देवली, काली घाटी और पांच पीपला के भारत मचार, अमर सिंह डामोर, राजेंद्र राणावत और शांतिलाल पारगी की बात कर रहे हैं। आप कभी आदिवासी बहुल देवली जाएं तो एक दुकान पर कम्प्यूटर के जरिए तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी और फॉर्म की उपलब्धता आश्चर्य में डाल सकती है। इस क्षेत्र में यूं तो आजीविका का साधन खेती, मजदूरी, मुर्गी पालन और बकरी पालन है, लेकिन खेती के लिए प्रति परिवार एक–दो एकड़ जमीन ही है। इसमें सालभर का गुजारा हो पाना मुश्किल है। क्योंकि इसमें केवल रबी की फसल ली जा सकती है। ऐसे में मजदूरी करना इन परिवारों की मजबूरी है, लेकिन इन चार युवाओं ने डिजिटल प्लेटफार्म की मदद से मजदूरी से मुक्ति पा ली।

यहां के ज्यादातर लोगों को मजदूरी के लिए गुजरात जाना पड़ता है। हम जिन चार युवाओं की आजीविका के साधन की बात कर रहे हैं, उनके लिए डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना मददगार साबित हुई। ग्राम पंचायत देवली, काली घाटी और पांच पीपला में संपर्क समाजसेवी संस्था और विकास संवाद भोपाल के सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत युवाओं और वंचित समुदाय के लोगों को डिजिटल तकनीक की जानकारी दी जाती है।

देवली में ई–दस्तक केंद्र ई–वालेंटियर और समुदाय के लोगों को डिजिटल तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। प्रयास यही था कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन हैं, वे ई–प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर अपने गांव और

आसपास की समस्याएं सुलझा सकें। इनकी ऑनलाइन शिकायत की सकें। वे अपने यहां की तमाम समस्याएं एक–दूसरे से शेयर कर सकें, जिससे इनका समाधान किया जा सके। गांव के लोग इसके लिए तैयार हुए। इनमें से चार युवाओं भारत मचार, अमर सिंह डामोर, राजेंद्र राणावत और शांतिलाल पारगी को आजीविका की दिशा मिल गई। उन्होंने ई–दस्तक केंद्र खोलना तय किया, ताकि वे लोगों की मदद के साथ ही अपने लिए कुछ कमाई भी कर सकें। अब वे रोजाना 300 से 400 रुपए तक कमा रहे हैं। उन्हें मजदूरी से मुक्ति भी मिल गई। वे गुजरात पलायन करने से भी बच गए। इस काम से उनके गांव के लोगों की मदद भी हो रही है। उन्हें सरकारी योजनाओं से जुड़े अपने कामों की जानकारी लेने और फॉर्म आदि भरने के लिए ब्लॉक तक नहीं जाना पड़ता है।

"ई–दस्तक केंद्र से मिली डिजिटल तकनीक बेहतर उपयोग की जानकारी के दम पर कई लोगों की मदद कर चुका हूं। मेरे इस मददगार रवैये के कारण गांव के लोगों ने मेरा नाम अतिथि शिक्षक के लिए दे दिया। मैं प्राइमरी स्कूल में अतिथि शिक्षक हूं। इससे मुझे 5000 रुपए मानदेय भी मिलता है।"

– नेपाल गामड

"ई–दस्तक केंद्र से टाइपिंग और एक्सल–वर्ड में काम करना सीखा। इसके दम पर मैं एक संस्था में नौकरी कर रही हूं। यहां से मुझे 7000 रुपए प्रतिमाह तनख्वाह भी मिलती है।"

– ललिता कटारा

ऑनलाइन वीडियो देखकर बदल दी किसानों की तकदीर

आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के कचरोटिया गांव के सुखराम भाभर डिजिटल पाठशाला लगाने के कारण काफी चर्चा में हैं। वे इस पाठशाला में यू–ट्यूब पर जैविक खेती करने के तरीकों से जुड़े वीडियो दिखाते और उन पर किसानों से बात करते हैं। उनकी क्लास में शामिल होने वाले किसानों को जैविक खेती के फायदे भी बताए जाते हैं। सुखराम किसानों को कम खर्च में अच्छी पैदावार और ज्यादा मुनाफे का गणित समझाते हैं। लोगों की मदद करते रहने के कारण गांव के सभी लोग सुखराम का सम्मान करते हैं। मजे की बात तो ये भी है कि सुखराम ने इस काम के लिए कहीं कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है और न ही कोई औपचारिक पढ़ाई की है। सुखराम ने बताया के उनसे जुड़ चुके एक दर्जन किसान जैविक खेती कर रहे हैं। ये सभी किसान कम लागत में ज्यादा पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।

सुखराम के गांव कचरोटिया में करीब 50 भील आदिवासी परिवार रहते हैं। इन परिवारों के पास दो से पांच बीघा तक जमीन है। आय का मुख्य साधन यही है, लेकिन इसमें इतनी पैदावार नहीं हो पाती कि परिवार का भरण पोषण सालभर हो सके। नतीजन, इन भील परिवारों को अपने गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर राजोद मजदूरी करने जाना पड़ता है। यहां काम मिल जाए तो 200 रुपए मजदूरी मिल जाती है। काम नहीं मिला तो निराश होकर लौटना पड़ता है। लगभग सभी भील परिवारों की यही दास्तां है। वे अपनी छोटी–छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हैं। कई बार तो इन्हें दूर शहर तक पलायन करना पड़ता है। पलायन करने वालों में सुखराम भाभर का बड़ा भाई लालू भाभर भी शामिल है। लालू के जाने के

बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुखराम पर आ गई है। उनके दो बच्चे भी हैं। ऐसे में परिवार चला पाना सुखराम के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। इस चुनौती से निपटने का रास्ता उन्होंने यू–ट्यूब से निकाल लिया।

सुखराम ने बताया कि वे विकास संवाद और संपर्क संस्था के सहयोग से गांव में बने ई–दस्तक केंद्र के जरिए इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वे डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना की बैठक में शामिल हुए तो उन्हें कुछ नया कर दिखाने की राह नजर आई। बैठक में डिजिटल तकनीक की ताकत और खूबियों को समझा। इसके बाद इसका इस्तेमाल करना सीखा। सुखराम डिजिटल तकनीक को समझते–समझते ई–वालेंटियर भी बन गए। इसके लिए उन्होंने ई–दस्तक केंद्र पर प्रशिक्षण लिया, जहां से यू–ट्यूब, फेसबुक, ट्वीटर आदि का उपयोग करना सीखे। बस, सुखराम के जीवन की दशा–दिशा यहीं से बदल गई। उन्होंने जैविक खेती करने का तरीका यू–ट्यूब पर सर्च किया और इससे जुड़े वीडियो देखे। सुखराम ने बताया कि अच्छी खासी लागत के बावजूद खेतों में कम पैदावार के कारण गांव का हर परिवार चिंतित था। खेती करना कई बार घाटे का सौदा साबित हो जाता था। ऐसे में वे कम लागत में अच्छी पैदावार वाली तकनीक अपनाना चाहते थे। सुखराम ने यह तकनीक यू–ट्यूब से सीखी। इसके बाद अपने एक बीघा खेत में प्रयोग किया और गांव के लोगों को इस मुहिम से जोड़ लिया।

सुखराम गांव के लोगों को जैविक खेती करने के तरीके यू–ट्यूब पर दिखाने लगे। इन तरीकों पर किसानों के साथ बात करते और जो उनके यहां की मिट्टी के अनुकूल होती उन पर काम करने की सलाह देते। इसके लिए उन्होंने एक स्थान तय कर लिया, जहां बैठकर हर शाम को जैविक खेती के वीडियो देखते और उसी की बात करते हैं। जिस एक बीघा जमीन पर उन्होंने जैविक खेती की थी, उसकी पैदावार अच्छी रही। इसके बाद गांव के अन्य किसान भी जैविक खेती करने लगे। हालांकि, कचरोटिया के ये भील आदिवासी यहीं नहीं रुके। अब वे जैविक खेती की नई–नई जानकारी हासिल करने के लिए यू–ट्यूब पर वीडियो देखते हैं। मोहन गरवाल ने बताया कि उन्होंने सुखराम से जानकारी लेकर एक एकड़ जमीन पर जैविक खेती की। इसमें कपास और सब्जियां लगाई। उन्हें कम लागत में अच्छी फसल मिल गई। सब्जियों का उत्पादन भी बहुत अच्छा रहा। इससे अच्छी आय हुई।

> **“सुखराम से मिली जानकारी के आधार पर मैंने एक एकड़ जमीन पर जैविक खेती की। इसमें कपास लगाया। रासायनिक खेती की अपेक्षा इसमें लागत कम आई और उत्पादन भी अच्छा मिला।”**
>
> **– बिजल भूरिया**

गायत्री ने ऑनलाइन बनाया इनोवेटिव लैंप

यू-ट्यूब से जुड़ा एक रोचक मामला खंडवा जिले के डाभिया गांव की गायत्री काजले का भी है। कुवरसिंह ने बताया कि गायत्री को बचपन से ही कुछ न कुछ नया करते रहे की आदत है, लेकिन गांव में ज्यादा सुविधाएं नहीं है। वहीं, परिवार की माली हालत खराब होने के कारण भी वे अलग से कोई सुविधा नहीं जुटा सकते, जिससे गायत्री अपनी कला का निखार सके। वह तो 12वीं की पढ़ाई करने भी करीब पांच किलोमीटर दूर पटाजन जाती है। हालांकि, गायत्री अब ई–वालेंटियर है। गायत्री रंगोली बनाने, सिलाई और कढ़ाई को आजीविका का साधन बनाना चाहती थीं।

गायत्री ने बताया कि उन्होंने ई–दस्तक केंद्र पर आकर यू–ट्यूब चलाना सीखा। साथ ही अपना मेल आईडी और गूगल अकाउंट बनाया। गायत्री ने यू–ट्यूब पर चाय के डिस्पोजल से लैंप बनाने का वीडियो देखा। वीडियो में यह काम एक महिला कर रही होती है, उसे देखकर गायत्री ने भी ऐसा लैंप बनाने का ठान लिया। इसके बाद एक शादी समारोह से निकले डिस्पोजल बीनकर ले आई और उनसे लैंप बनाने का प्रयास किया, जिसमें गायत्री सफल रही। अब गायत्री इस काम में आजीविका तलाश रही है। वहीं, गांव की महिलाओं को डिजिटल तकनीक का उपयोग करना और इसके माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान निकलना सिखा रही हैं।

सामाजिक मुद्दों और समस्याओं पर एक माह में शेयर किए 58 वीडियो

डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के तहत ई–वालेंटियर बने संजीव अहिरवार ने सरकारी योजनाओं के जिम्मेदारों और इन योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों के बीच की खाई को सोशल मीडिया के जरिये पाटने के अच्छे प्रयास किए हैं। संजीव बताते हैं कि उन्हें इस काम के लिए ई–दस्तक केंद्र से काफी मदद मिली। उन्होंने एक माह के भीतर 58 वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए। ये सभी वीडियो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए थे। संजीव ने ये वीडियो फेसबुक, ट्विटर और वाट्सएप पर वायरल करने के साथ ही यू–ट्यूब पर भी शेयर किए। यू–ट्यूब पर तो उन्होंने अपना चैनल ही शुरू कर दिया। इससे कई समस्याओं का समाधान भी निकला। उन्होंने इन वीडियो में समस्याओं के अलावा गांव में किए जा रहे अच्छे कार्यों को भी शामिल किया। इससे कई समस्याएं सीधे जिम्मेदारों तक पहुंच गई, जिससे इनका समाधान हो गया।

संजीव पन्ना जिले की बुजपुर ग्राम पंचायत के बृजपुर गांव गिरवानी टोला में रहते हैं। संजीव प्राइवेट नौकरी करते हैं, जिससे 14000 रुपए प्रतिमाह मिल जाते हैं। उन्होंने बीएड किया है। इस टोले में अहिरवार समाज के 100 परिवार हैं। 10 परिवार आदिवासी और करीब 60 अन्य परिवार इस टोले में निवास करते हैं। अधिकतर परिवारों की आय का जरिया मजदूरी है। कुछ परिवारों के पास खेती है, लेकिन इससे सालभर का गुजारा करने लायक उपज नहीं हो पाती। इसलिए, मजदूरी करना पड़ता है। गिरवानी टोले में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। पानी की टंकी तो बनी है, लेकिन पाइपलाइन नहीं होने के कारण घरों तक सप्लाई नहीं है।

संजीव ने बताया कि अब वे गांव की तमाम तरह की समस्याओं का

निराकरण कराने के लिए इनके वीडियो बनाकर जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा देते हैं। इससे उन्हें पता चल जाता है कि गांव में क्या समस्या है और गांव के लोग इनके बीच किन विकट परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं। ये वीडियोज गांव के युवा भी देखते हैं और वे इसी तरह के वीडियो बनाना सीख चुके हैं। हालांकि, संजीव का कहना है कि वे गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जन सरोकारी पहल से जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर लाना जरूरी है। वे प्रयास करते हैं कि गांव के अन्य युवा भी उनकी तरह सोशल मीडिया पर वीडियोज शेयर करें। संजीव का उद्देश्य यू–ट्यूब के जरिये पैसा कमाना भी है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग यू–ट्यूब पर वीडियोज डालकर पैसे कमा रहे हैं। वे स्वयं भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि जनसरोकार के मुद्दों से भी जुड़े रहें और कुछ आमदनी भी होती रहे।

संजीव ने बताया कि उनके यू–ट्यूब चैनल के 60 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। सामाजिक मुद्दों पर बनाए गए उनके वीडियोज को हजारों लोग देख चुके हैं। इसलिए, उन्हें विश्वास है कि ये चैनल और अच्छी तरह चल सकता है, जिससे आमदनी भी होगी। संजीव को कॉमेडी का शौक भी है। वे स्वयं कॉमेडी कर लेते हैं, इसलिए वीडियोज में इसे भी शामिल कर रखा है, ताकि गांव की समस्याओं को हास्य के साथ पेश किया जा सके।

संजीव के इस कौशल और पहल के पीछे ई–दस्तक केंद्र की अहम भूमिका है। वे ई–दस्तक केंद्र पर कौशल विकास की क्लास में शामिल होते रहे हैं, जहां से सोशल मीडिया की बारीकियां सीखीं। उन्होंने बताया कि ई–दस्तक केंद्र पर जाते रहने से उनकी समझ विकसित हुई और आत्मविश्वास बढ़ा है। इसके बाद वे समाजसेवा करने के लिए प्रेरित हुए हैं। यहां सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, फोटो खींचने, वीडियो बनाने का तरीका, कैमरा हैंडल करना, ट्विटर अकाउंट बनाना, ट्वीट करना, जरूरी हेल्पलाइन नंबर, आधार कार्ड व समग्र आईडी से जुड़े काम, ऑनलाइन आवेदन करना आदि शुरू कर दिया। संजीव इन सभी जरियों से गांव के लोगों की मदद भी करते हैं।

समाज के लिए ऐसे किया सोशल मीडिया का इस्तेमाल

संजीव ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने परिवार से लेकर मोहल्ले और फिर पूरे गांव की मदद की। अपनी बहन रीना को सिलाई से जुड़े नए डिजाइन वाले वीडियो दिखाए। इससे रीना को काफी मदद मिली। वह नए डिजाइन सीख गई। इसके बाद संजीव ने छुआछूत सहित सामाजिक कुरीतियों से जुड़े वीडियो तैयार किए। ये वीडियो काइन मास्टर से तैयार किए। इसके बाद अपने यू–ट्यूब चैनल पर शेयर कर दिए। इनका अच्छा रेस्पॉन्स मिला।

संजीव ने बताया कि पंचायती राज से जुड़ी जानकारी खुद अपने लिए और गांव वालों के लिए बेहद जरूरी थी, इसलिए यह जानकारी गूगल पर सर्च की और गांव वालों को भी जागरूक किया। गांव की समस्याओं और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से जुड़े वीडियो यू–ट्यूब पर शेयर किए। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। इसके बाद कई समस्याओं का समाधान हुआ। इसके अलावा गांव के लोगों को डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना से जोड़ रहे हैं। वे रवि अहिरवार और रवीन्द्र

अहिरवार को भी ई–वालेंटियर बना चुके हैं। अब रवि और रवीन्द्र भी सामाजिक मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं।

ऐसे जुड़े डिजिटल तकनीक से

संजीव अहिरवार मार्च 2018 में ई–वालेंटियर बने। इस दौरान उनके गांव बृजपुर में बेसलाइन सर्वे चल रहा था। ई–वालंटियर के चयन के लिए सामुदायिक बैठकों का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान संजीव ने सर्वे टीम से डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना का मकसद समझा। तमाम जानकारी लेने के बाद संजीव ई–वालंटियर बन गए, तब तक सामाजिक मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल संजीव ने नहीं किया था। ई–दस्तक केंद्र पर कौशल विकास क्लास के बाद संजीवन इस दिशा में भी सक्रिय हो गए।

"संजीव गांव के मुद्दों से जुड़े वीडियो यू–ट्यूब पर डालते रहते हैं। हमें डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करना उन्हीं ने सिखाया है। उनकी मदद से अब मैं भी जनहित के मुद्दों पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करता हूं।"

– रवि

"संजीव से कई जरूरी जानकारियां मिली हैं। अब मैं भी महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देती हूं। उनको स्वरोजगार से जुड़े वीडियो यू–ट्यूब पर दिखाती हूं। गांव के कई लोग मुझसे सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने भी आते हैं।"

– रीना

ट्वीट से आई बिजली और मिली साइकिल तो खुली स्कूल की राह

आपको यह जानकार हैरत होगी कि मध्यप्रदेश में हर साल तीन लाख से अधिक बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में तमाम सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का दावा किया जाता है। हालांकि, हकीकत इससे जुदा है। निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म और मध्याह्न भोजन भी उन्हें लुभाने में नाकाम रहा है। पन्ना के शासकीय माध्यमिक शाला मकरी कुठार का मामला जरा हटकर है। यहां के बच्चे स्कूल में बिजली नहीं होने के कारण पढ़ाई छोड़ रहे थे। जब बच्चों से स्कूल छोड़ने का कारण पूछा गया तो उन्होंने इसमें बिजली और पंखा नहीं होना बड़ा कारण बताया। इसके बाद डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के ई–वालंटियर ने इस समस्या का समाधान सुझाया। डिजिटल प्लेटफार्म पर शिकायत के बाद स्कूल में बिजली लग गई और बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ गई। इस तरह स्कूल छोड़ने का एक अन्य मामला पन्ना जिले के भटिया टोला ग्राम धानौजा बृजपुर का है, जिसमें निःशुल्क साइकिल नहीं मिलने के कारण एक लड़की का स्कूल जाना मुश्किल हो गया। इससे पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। स्कूल उनके टोले से पांच किलोमीटर दूर था। इसके बावजूद उसे अपात्र घोषित कर साइकिल नहीं दी गई। हालांकि, बाद में एक ट्वीट के दम पर उसे साइकिल मिली और वह स्कूल जाने लगी।

चूंकि मकरी कुठार में ज्यादातर परिवार आदिवासियों के हैं। यहां रहने वालों में से महज 20 फीसदी लोग ही डिजिटल तकनीक का उपयोग करना जानते हैं। मकरी कुठार गांव में तो बिजली थी, लेकिन यहां के स्कूल में बिजली कनेक्शन नहीं था। इससे पंखे नहीं चलते थे। नतीजन, गर्मी के कारण बच्चे क्लास में बैठने में रुचि नहीं ले रहे थे। बात सिर्फ

स्कूल में उपस्थिति कम होने की नहीं थी, इन बच्चों के भविष्य का भी सवाल था। डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना की टीम स्कूल पहुंची तो वहां करीब 35 बच्चे मिले, उनसे स्कूल में अरुचि का कारण पूछा तो उन्होंने पंखे नहीं चलना और गर्मी लगना बताया। हालांकि, उनसे आगे बातचीत की गई तो समस्याएं और भी सामने आईं। बच्चों ने बताया कि गर्मी के कारण कुछ बच्चे बीमार पड़ने लगे थे, इसलिए वे स्कूल नहीं आ रहे हैं। अजय ने बताया कि हमारे स्कूल में बैठने के लिए टाट पट्टी कम हैं। हमें फर्श पर बैठना पड़ता है। वहीं, जयंती ने कहा कि हमारी कक्षा में बारिश के दिनों में पानी टपकता है। इसके कारण बरामदे में क्लास लगाई जाती है।

बच्चों की समस्याएं सुनने के बाद स्टाफ और गांव के लोगों को बताया गया कि वे सीएम हेल्पलाइन 181 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। ट्वीट करके कलेक्टर को तमाम समस्याएं बता सकते हैं। इतना ही नहीं वे अभ्योदय योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली जनसुनवाई में भी अपनी समस्या रख सकते हैं। सोशल मीडिया के दूसरे माध्यमों के जरिये भी इन समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचा सकते हैं। इससे समाधान जरूर होगा। बच्चों ने बताया कि वे ट्वीट और फेसबुक के बारे में नहीं जानते हैं। इसके बाद डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना की टीम ने बच्चों को ट्विटर की जानकारी दी। इसके बाद रेवा गोंड ने ट्विटर और विनोद गुप्ता ने फेसबुक पर बिजली न होने की समस्या पोस्ट की। इससे पन्ना कलेक्टर को टैग कर दिया। इस पर कलेक्टर ने मामले की गंभीरता समझी और सभी संकुल प्राचार्यों की बैठक लेकर एक सप्ताह के अंदर स्कूलों में बिजली कनेक्शन देने के आदेश दिए।

स्कूल के प्रधान पाठक ने कहा कि आप इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की जो जानकारी लोगों को दे रहे हैं, यह बहुत सराहनीय कार्य है। आप लोगों के कारण ही हमारे स्कूल में बिजली कनेक्शन लग सका। आपने इस मामले को ट्विटर पर उठाया तो कलेक्टर ने भी गंभीरता से लिया। इसी का नतीजा है कि आज स्कूल रोशन है।

एक ट्वीट से मिली नंदनी को साइकिल

पन्ना जिले के भटिया टोला ग्राम धानौजा बृजपुर निवासी सुरेश गोंड की बेटी नंदनी को सरकारी योजना की निःशुल्क साइकिल नहीं मिली तो स्कूल आने–जाने की समस्या खड़ी हो गई। वह बृजपुर में कक्षा सातवीं में पढ़ती है। छटवीं में साइकिल योजना के लिए पात्र होने के बावजूद नंदनी को साइकिल नहीं दी गई थी। उसे अपात्र घोषित कर दिया गया था। नंदनी का स्कूल भटिया टोला से पांच किलोमीटर दूर है। इतनी दूर अकेले पैदल जाना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। वह कई दिनों तक स्कूल नहीं गई, जिससे पढ़ाई प्रभावित होने लगी। छोटी सी किराना दुकान चलाकर परिवार का पालन–पोषण कर रहे सुरेश के लिए साइकिल खरीदकर दे पाना भी आसान नहीं था। ऐसा नहीं था कि भटिया टोला में अकेले नंदनी को साइकिल नहीं मिली थी। कुछ और भी छात्राएं थीं, जिन्हें अपात्र घोषित कर साइकिल नहीं दी गई। इससे वे स्कूल नहीं जा पा रही थीं। सुरेश ने साइकिल नहीं मिलने की जानकारी ई–दस्तक केंद्र में दी। उन्होंने यह भी बताया कि तमाम कागजात पूरे थे, इसके बावजूद नंदनी को अपात्र घोषित किया गया। उन्होंने पंचायत सचिव और सरपंच से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ई–दस्तक केंद्र की टीम ने

नंदनी के दस्तावेज जांचे, इनके आधार पर वह साइकिल के लिए पात्र थी।

ई–दस्तक केंद्र से सुरेश को बताया गया कि नियमानुसार जिनके घर स्कूल से दो किलोमीटर या इससे अधिक दूर हैं, उनको साइकिल दी जाती है। यह योजना छटवीं से नौवीं तक प्रवेश लेने वालों के लिए है। उनसे कहा गया कि वे सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि, ई–वालेंटियर काजल ने गांव के 12 लोगों की सूची ट्वीट कर दी। इसके बाद जांच हुई। जांच में खुलासा हुआ कि ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण ये बच्चे साइकिल से वंचित हुए थे। इनके समग्र आईडी में धानौजा की जगह ग्राम बृजपुर लिख दिया गया था, इसलिए इन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। काजल ने पन्ना कलेक्टर को भी ट्वीट से जोड़ा था। इसके बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया और नंदनी को साइकिल मिल गई।

खुद का काम शुरु किया तो बच्चों की शिक्षा में आया सुधार

महज आधा एकड़ कृषि भूमि के मालिक पुष्पेंद्र डामर को परिवार का पालन–पोषण करने के लिए पलायन करना पड़ता था। वे अपने खेत में कपास और मक्का लगाते हैं। खेत में इतनी फसल नहीं हो पाती है कि वे इससे सालभर गुजारा कर सकें, मजबूरन उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ता था। इससे परिवार भी परेशान रहता था। सबसे ज्यादा बुरा असर तो उनके बच्चे की पढ़ाई पर पड़ रहा था। वे पढ़ाई नियमित नहीं कर पा रहे थे। पुष्पेंद्र जब मजदूरी के लिए बाहर जाते तो परिवार भी उनके साथ जाता था। जाहिर है, इससे उनके बच्चों भविष्य पर बुरा असर पड़ना तय था, लेकिन पुष्पेंद्र के पूरे परिवार की समस्याओं का हल ई–दस्तक केंद्र की एक सलाह पर हो गया। पुष्पेंद्र के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे यानी चार सदस्य हैं। वे झाबुआ जिले के पेटलावद ब्लॉक की देवली पंचायत के गांव झरनिया में रहते हैं।

पुष्पेंद्र ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत देवली में विकास संवाद और संपर्क संस्था के सहयोग से डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना का काम किया जा रहा था। इसके तहत यहां ई–दस्तक केंद्र खोला गया है। यहां की डिजिटल टीम गांव के लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं सहित स्वरोजगार की की जानकारी देती है। इनके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। पुष्पेंद्र ने बताया कि उन्होंने ई–दस्तक केंद्र के लोगों से बात की तो उन्होंने किराना दुकान खोलने की सलाह दी। इस पर पुष्पेंद्र ने कहा कि किराना दुकान नहीं चलेगी। दुकान खोलने के बाद वे मजदूरी करने बाहर भी नहीं जा सकेंगे। ऐसे में दुकान नहीं चलती है तो परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। इस तरह के कई बुरे ख्याल पुष्पेंद्र के दिमाग में

आने लगे। उनकी तमाम बातें सुनने के बाद ई–दस्तक केंद्र की टीम ने कहा कि किसी भी काम में जोखिम तो उठाना पड़ता है। उन्हें बताया गया कि इस तरह का खतरा तो सभी मामलों में रहता है। यदि व्यवसाय शुरू करने से पहले सभी लोग इस तरह डर जाते तो तरक्की कैसे कर पाते। इसलिए, डरने की जरूरत नहीं है।

ई–दस्तक केंद्र की सलाह पर पुष्पेंद्र ने अपने गांव झरनिया में किराना दुकान खोल ली। शुरुआत में कुछ दिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद उन्हें 200–250 रुपए प्रतिदिन बचत होने लगी। इस तरह पुष्पेंद्र अपने गांव में ही खुद का रोजगार करने लगे। अब उन्हें मजदूरी करने दूसरे राज्यों में भी नहीं जाना पड़ता है। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई का क्रम भी बीच में नहीं टूटता है। इससे वे अच्छी तरह पढ़ पा रहे हैं। अच्छी बात तो यह भी है कि पुष्पेंद्र खुद अब लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने की सलाह देते हैं। इसके लिए ई–दस्तक केंद्र की टीम से मिलने और प्रशिक्षण लेने का रास्ता बताते हैं।

अतरवती बनीं महिलाओं की हमदर्द

महिला सशक्तिकरण विभाग ने भोपाल की मीरा नगर बस्ती में रहने वाली 40 वर्षीय अतरवती चौहान को रानी अवंति बाई सम्मान से नवाजा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी खुशी को तालियों की गड़गड़ाहट ने कई गुना बढ़ा दिया। गांधी भवन में 16 अगस्त 2018 को मिले इस सम्मान को अतरवती आखिरी सम्मान नहीं मानती हैं। यही वजह है कि उन्होंने वे तमाम काम बंद नहीं किए, जिनके लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। यह सम्मान उन्हें अदम्य साहस, इच्छाशक्ति और दूसरों की मदद करने के जज्बे के दम पर मिला है। वे पीड़ित और वंचित महिलाओं व बालिकाओं की हमदर्द बनकर उभरी हैं। अतरवती सक्रिय रक्षा महिला समूह और शौर्या दल की करीब तीन साल से धाकड़ सदस्य हैं। अतरवती कहती हैं महिलाओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें तमाम विकट परिस्थितियों से खुद ही लड़ना होगा। रसूखदारों को तो कई मददगार मिल जाते हैं, लेकिन कमजोरों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। इनकी मदद करना बड़ी चुनौती है। मैं उनके साथ खड़ी हूं और लगातार मदद भी कर रही हूं। उनका भोपाल पहुंचना और यहां खुद के साथ दूसरों के लिए संघर्ष करने की कहानी बेहद रोचक और प्रेरणास्पद है।

अतरवती बताया कि वे मूलतः छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं। उनका परिवार करीब 15 साल पहले काम की तलाश में भोपाल आया था, जो यहां वार्ड 50 की मीरानगर बस्ती में रहने लगा। वहीं, रक्षा महिला समूह की सदस्य बन गईं। अतरवती के पति निर्माण कारीगर हैं। बेटा और बेटी आदर्श युवा समूह के सदस्य हैं। अतरवती को कुछ समय बात बस्ती की तमाम तरह की समस्याओं की जानकारी मिली। इससे वे बहुत चिंतित थीं। उनकी

चिंता का हल डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना से जुड़ने के बाद निकला। यहां से उन्होंने आंगनवाड़ी की पोषण आहार समिति और शौर्या दल की सदस्यों के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090, सीएम हेल्पलाइन नंबर 181, पुलिस बुलाने के लिए डॉयल 100, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 सहित तमाम जरूरी जानकारी विस्तार से हासिल की। इसके बाद बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं की मदद करने लगीं। यह सिलसिला आज भी जारी है।

बात करीब तीन साल पुरानी है। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर दी। यह जानकारी अतरवती को मिली तो उन्होंने आरोपी पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। उसके पांच बच्चे थे, जिन्हें अतरवती ने सरकारी गृह में रखवा दिया और पढ़ाई शुरू करवा दी। अतरवती ने आज भी इन बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। वे अब भी जाकर उनसे मिलती हैं और तमाम जानकारी लेती रहती हैं। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए संवेदनशील अतरवती के पास खुद का स्मार्टफोन भी है, जिसके माध्यम से छोटे–बड़े कई काम कर लेती हैं। बच्चों और महिलाओं को तमाम तरह की हिंसा से बचाने के लिए टोल फ्री नंबर का उपयोग करती हैं। अतरवती ने बताया कि जब उन्हें डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के माध्यम से हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी मिली तो खुद को एक अलग तरह की ताकत से भरा हुआ पाया। इसके बच्चों और महिलाओं की मदद में पुलिस बुलाना और महिलाओं की मदद करना आसान हो गया। इससे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी बेटी नीलम को भी स्मार्टफोन दिलवा दिया है। उनकी बेटी भी अतरवती की तरह सक्रिय है। अतरवती लड़कियों को इंटरनेट से सावधान रहने रहने की बात करती हैं, लेकिन उन पर पाबंदी के खिलाफ हैं। उन्होंने नीलम की मदद से सोशल मीडिया का उपयोग करना सीख लिया है। अतरवती मोबाइल फोन को महिला सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साधन मानती हैं, इसलिए अपने समूह और शौर्या दल की साथी महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी देती हैं।

बालिका का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया

अतरवती ने बताया कि पिछले साल उत्तर प्रदेश से एक नाबालिग बालिका को अगवा कर भोपाल लाया गया था। उसे मीरा नगर बस्ती में ही रखा गया था। वह नाबालिग जैसे–तैसे छूटकर भाग रही थी, जिस पर अतरवती की नजर पड़ गई। अतरवती ने तत्काल डॉयल 100 पर कॉल किया और पुलिस बुला ली। इसका नतीजा यह रहा कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया और बच्ची के रहने की व्यवस्था बालिका सुधार गृह में करवा दी। अतरवती यहीं शांत नहीं बैठीं, वह लगातार फॉलोअप लेती रहीं। करीब दो साल बाद उसे उसके घर उत्तर प्रदेश पहुंचा दिया गया। इस तरह अतरवती की मदद से एक बालिका का जीवन बर्बाद होने से बच गया। एक अन्य मामला बस्ती की उस महिला का है, जिसे उसके पति ने हथियार से मारा था। अतरवती ने डॉयल 100 बुलाई और उस व्यक्ति को जेल भिजवा दिया। इसके बाद चंदा करके रुपए जुटाए, जिससे महिला का इलाज कराया। चूंकि, वह गंभीर रूप से जख्मी थी, इसलिए उसके ठीक होने तक करीब तीन माह उसके बच्चों की खाने और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई। हालांकि, इस काम में समूह की मदद ली

थी। अतरवती ने बताया कि उनके दल में पांच लड़के भी हैं, लेकिन वे ज्यादा काम नहीं करते। कई मामलों में डर जाते हैं, लेकिन हम महिलाएं धैर्य और सूझबूझ के साथ लोगों की मदद करती हैं। अब मेरे स्मार्टफोन में हेल्पलाइन नंबरों के अलावा भोपाल के कई गैरसरकारी संगठनों के नंबर भी हैं, जो बच्चों और महिलाओं के हक में काम कर रहे हैं। अतरवती खुद वाट्सएप मैसेज भेज सकती हैं। अतरवती ने पिछली जुलाई में मीरा नगर बस्ती के जर्जर आंगनवाड़ी भवन का मुद्दा मीडिया के सामने उठाया। इस तरह ये मामला जिम्मेदारों तक पहुंचा। इसके बाद अगस्त में उनके पति अचानक कहीं चले गए तो उन्हें खोजने के लिए अतरवती ने बेटी की मदद से सोशल मीडिया पर कई मैसेज शेयर किए। इससे कुछ बाद दिन वे लौटकर आ गए।

जानकारी जुटाती रहती हैं

अतरवती भोपाल में होने वाली विभिन्न संस्थाओं की बैठकों में शामिल होती हैं, जहां से तमाम तरह की जरूरी जानकारी जुटा लेती हैं। वे स्मार्टफोन होने से पहले इनकी हार्डकॉपी अपने घर में रखती थीं, ताकि जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग कर सकें। लेकिन, इनके खराब होने का भी डर रहता था। अब स्मार्टफोन है तो वे तमाम जरूरी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर लेती हैं। यही वजह है कि वे महिलाओं पर इंटरनेट की पाबंदी के खिलाफ नहीं हैं।

“अतरवती गांव की महिलाओं के उत्थान के लिए अच्छा काम कर रही है। अगर हमें कोई समस्या आती है तो उन्हीं की मदद लेते हैं। फिर मामला महिला हिंसा का हो या अन्य कोई भी, हमें हरसंभव मदद मिल जाती है।”

– अनिता कुशवाह

“अतरवती सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। समुदाय की महिलाओं को सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूक करती रहती हैं।”

– चित्ररेखा

यू-ट्यूब से समझे बीमारी से बचाव के उपाय

भोपाल के पीसी नगर में रहने वाली 19 वर्षीय मोहनी कुशवाहा का जीवन संषर्घों से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने हौसले को लगातार और अधिक मजबूत करती रहीं। मूलतः विदिशा जिले की रहने वाली मोहनी का परिवार काम की तलाश में भोपाल आया था। यहां तीन हजार रुपए महीना किराए पर कमरा लेकर रहता था। मोहनी के जीवन में पहली बड़ी परेशानी तब आई, जब उनके सिर से पिता का साया उठ गया। इसके बाद मां और मोहनी एक–दूसरे का सहारा थीं। हालांकि, मां इस घटना के बाद छोला में नानी के घर चली गई। मां भी ज्यादा दिन साथ नहीं रहीं। टीबी ने ऐसा घेरा कि मां का साया भी मोहनी के सिर से उठ गया और वह पूरी तरह अकेली हो गई। मां के इलाज और क्रियाकर्म के लिए भी मोहनी को कर्ज लेना पड़ा। इस बीच डिजिटल प्लेटफार्म ने मोहनी की काफी मदद की। वह अपनी मां के इलाज और सावधानी से जुड़ी तमाम जानकारी ऑनलाइन सर्च करती थीं। उन्होंने यू–ट्यूब पर टीबी से बचाव की सावधानियों को समझा और फॉलो किया। हालांकि, मां की देखभाल करते–करते मोहनी को भी टीबी ने घेर लिया था।

मोहनी ने बताया कि जब मां को हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया था, तक डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी। इस कारण उन्हें समय पर उचित इलाज नहीं मिल सका। मोहनी को स्वयं ज्यादा देखभाल करना पड़ा। जब मोहनी को भी टीबी हुई तो उन्होंने यू–ट्यूब का भी सहारा लिया जिससे वह जल्दी ही ठीक हो गई। यू–ट्यूब की जानकारी उन्हें ई–वालंटियर अनिता कुशवाहा से मिली थी। अनिता ने मोहनी को इंटरनेट इस्तेमाल करना सिखाया था। चूंकि पिता की मृत्यु के बाद मोहनी

की पढ़ाई छूट गई थी, इसलिए अब वह दूसरों के घरों में काम करके अपना खर्चा निकालती हैं। हालांकि, यह काम भी लगातार नहीं मिलता, इसलिए कई बार कर्ज की नौबत आ जाती है। मोहनी ने कर्ज तो उस समय भी लिया था जब उनकी मां का देहांत हुआ था। तब मोहनी ने 5000 रुपए अपने जीजा और अपने जीजा से उनसे लिए जिनके यहां काम करने जाती थी। इससे मां का क्रियाकर्म और रसोई कराई थी। इस काम के लिए उन्हें विदिशा जाना पड़ा था।

मोहनी कुशवाहा
(ई-वालंटियर)

अब मोहनी चाहती है कि उन्हें किसी सरकारी योजना के तहत घर मिल जाए। इसके लिए अपने स्मार्टफोन पर यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं की जानकारी सर्च करती रहती हैं। यह सलाह मोहनी को ई-वालेंटियर मंजू ने दी थी। मोहनी ने बताया कि उनके जीजा की आय भी इतनी नहीं है कि वह मदद कर सके। तमाम परेशानी के दौरान मोहनी पर 20000 रुपए का कर्ज हो गया, जिससे अब कमरे का किराया देते रहने की स्थिति नहीं बची। अब वह अपनी नानी के यहां जाना चाहती है।

पूजा ने पाई अनजान नंबर से कॉल और मैसेज से मुक्ति

पूजा शाह का परिवार करीब चार साल पहले बिहार से काम की तलाश में भोपाल आया। उनके पति राजू शाह टाइल्स लगाने का काम करते हैं, जिससे छह से आठ हजार रुपए मासिक मिल जाते हैं। उनकी दो बेटियां हैं। 23 वर्षीय पूजा का परिवार वार्ड 50 की ईश्वर नगर बस्ती में किराए से रहता है। पूजा को अपनी बस्ती में डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के तहत आयोजित सामुदायिक बैठक में स्मार्टफोन और इंटरनेट के फायदे मालूम पड़े तो उन्हें लगा कि एक स्मार्टफोन होना चाहिए, जिससे वह कई काम खुद घर बैठे कर सकती हैं। इससे दूसरों की मदद भी कर सकेंगी। बैठक में तमाम बारीकियां समझने के बाद पूजा ने राजू से स्मार्टफोन खरीदवा लिया। हालांकि, राजू स्मार्टफोन दिलाने के पक्ष में नहीं थे। उनका तर्क था कि जब कभी कॉल करने की जररूत पड़े तो उनके ही फोन से कर लिया करे। इस पर पूजा ने स्मार्टफोन और इंटरनेट की खूबियां बताई और जिद की तो राजू मान गए। यहां तक सबकुछ ठीक चल रहा था, लेकिन परेशानी उस दिन खड़ी हो गई, जिस दिन पूजा के फोन पर अनजान व्यक्ति कॉल करने लगा। हालांकि, इसका समाधान भी पूजा ने अपने फोन से ही निकाला, लेकिन तब तक का किस्सा बड़ा रोचक रहा।

पूजा को मार्च 2018 में आयोजित सामुदायिक बैठक में डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना की जानकारी मिली। इसके बाद वह निवसीड संस्था की ओर से आयोजित बैठकों में शामिल होने लगीं। पूजा ने बताया कि इन बैठकों और संस्था के कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन सर्च करना आ गया। उन्होंने नगर निगम की तमाम

योजनाओं की जानकारी भी सर्च करके देखी। संस्था के साथियों ने उन्हें इंटरनेट सर्फिंग सिखा दी, जिससे अब वह तमाम तरह की जानकारी खुद सर्च कर लेती हैं। उन्हें यू–ट्यूब, गूगल, ई–मेल, वीडियो कॉलिंग, फोटो एडिटिंग आदि की बुनियादी जानकारी यहीं से मिली। उन्होंने बताया कि बस्ती में किशोरी महिला समूह की बैठक में उन्हें ई–वालेंटियर की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने ई–वालेंटियर बनने का निश्चय किया, लेकिन इसके लिए स्मार्टफोन जरूरी था। यह स्मार्टफोन उन्होंने अपने पति राजू से जिद करके ले लिया। हालांकि, पूजा की सक्रियता को देखते हुए उन्हें ई–वालेंटियर बनाने का विचार संस्था के लोगों के मन में भी आया था।

ई–वालेंटियर पूजा ने महिला हेल्पलाइन 1090 और 1091 के बारे में विस्तार से समझा। इससे जुड़ी जानकारी इंटरनेट पर सर्च की। पूजा ने बताया कि एक दिन संस्था की कार्यकर्ता सुनीता सतनकर उन्हें बुलाने घर पहुंचीं, तब पूजा ने बताया कि एक अनजान नंबर से बार–बार कॉल आ रहे हैं। संबंधित व्यक्ति वाट्सएप अभद्र टिप्पणी कर रहा है। उसके कॉल और मैसेज से वह तंग आ चुकी है। चूंकि पूजा ने मोबाइल फोन पति से जिद करके लिया था, इसलिए उन्हें सीधे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर भी जब उन्होंने राजू को बताया तो वे नाराज हुए। बोले– मैंने पहले ही समझाया था। स्मार्टफोन मत लो, लेकिन तुमने जिद की। राजू का लगता था कि ये सारी दिक्कतें स्मार्टफोन की वजह से हैं। पूजा ने ये तमाम बातें सुनीता को बताने के साथ ही महिला समूह की बैठक में भी सांझा की। समूह की महिलाओं ने पूजा को महिला हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने को कहा। पूजा ने जब शिकायत के लिए कॉल किया तो उसे अच्छा रेस्पॉन्स मिला, जिससे न्याय की उम्मीद जागी। इस दौरान पूजा ने यह कॉल रिकॉर्ड भी कर लिया। पूजा ने अनजान नंबर से कॉल और मैसेज आने की तमाम जानकारी कॉल रिसीव करने वाली महिला को बताई। कॉल के बाद पूजा के फोन पर मैसेज आया कि उनकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। संबंधित व्यक्ति को समझाइश दी जाएगी। इसके बावजूद नहीं मानता है तो पुलिस में मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूजा ने यह बात राजू को बताई तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। इसके बाद पूजा ने राजू को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई। हालांकि, एक शिकायत के बाद पूजा के पास फिर कभी उस नंबर से कॉल या मैसेज नहीं आया। पूजा ने पूरा घटनाक्रम महिला समूह की बैठक में साझा किया, जिससे अन्य महिलाओं का हौसला अफजाई हुआ।

आरती ने भी पाया ब्लैंक कॉल से छुटकारा

आरती
(ई–वालंटियर)

भोपाल के पीसी नगर में बीडीए की मल्टी में रहने वाली आरती परतेती भी अननोन नंबर की कॉल से परेशान थी। आरती ने इसका समाधान भी अपने मोबाइल फोन से ही किया। चूंकि आरती स्मार्ट युवा समूह की सदस्य हैं और जनवरी 2018 से डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना में ई–वालेंटियर भी हैं, जिससे उन्हें ई–प्लेटफार्म महत्व मालूम है। उन्होंने ई–दस्तक केंद्र पर तमाम तरह की जानकारी हासिल की है। इसके बाद महिला सुरक्षा और उनसे

जुड़े कानूनों को लेकर वह काफी जागरूक हुई हैं। जब उन्होंने अपनी ही समस्या का समाधान सबसे पहले किया तो उनका हौसला और बढ़ गया। आरती ने बताया कि मार्च 2018 की बात है, एक व्यक्ति ने उन्हें कॉल किया। आरती उसे पहले से नहीं जानती थी। शुरू में आरती ने उसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब वह लगातार कॉल करने लगा तो आरती परेशान रहने लगी। यह परेशानी आरती ने पीसी नगर में आयोजित पीएलए बैठक में साझा की। बैठक में संस्था की कार्यकर्ता मंजू ने आरती को महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में बताया। उन्होंने इस नंबर पर शिकायत करने की सलाह दी। आरती ने 1090 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आरती के पास उस शख्स का कॉल दोबारा कभी नहीं आया। इस तरह एक समस्या हल होने के बाद आरती की हिम्मत बढ़ी तो वह दूसरी महिलाओं और युवतियों की मदद करने लगी। अब तो फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी सक्रिय हैं। इनके जरिए कई महिलाओं से जुड़ी हैं।

ई–दस्तक केंद्र ने दिलाया पूरा राशन

पन्ना जिले के रखेल टोला में रहने वाले धीरेंद्र गोंड तमाम दूसरे आदिवासी युवाओं की ही तरह हैं। धीरेंद्र के परिवार में छह सदस्य हैं। चूंकि परिवार बड़ा है, तो खर्चे भी ज्यादा हैं। धीरेंद्र और उनकी पत्नी मजदूरी करते हैं। माली हालत के आधार पर वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले 20 राशन के हकदार हैं, लेकिन उन्हें पूरा राशन नहीं दिया जा रहा था। पढ़ा–लिखा कम होने क कारण धीरेंद्र को इस बात का भी इल्म नहीं था कि दुकान से राशन कम दिया जाए तो शिकायत कहां करें। इसका समाधान कहां से करवाएं। दूसरी समस्या यह भी थी कि शिकायत करने के चक्कर में एक दिन की मजदूरी का नागा हो जाएगा। और, सच तो यह है कि धीरेंद्र को यह भी नहीं मालूम था कि वह कितने राशन का पात्र है। उनके परिवार में पत्नी, तीन बेटियां और एक बेटा है।

धीरेंद्र ने बताया कि जनवरी 2018 की बात है। डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के ई–दस्तक केंद्र की टीम उनके गांव में सर्वे कर रही थी। ई–दस्तक केंद्र के साथियों से उनकी मुलाकात हुई। धीरेंद्र का परिचय हुआ और ई–दस्तक केंद्र से जुड़ी कुछ जानकारी हासिल की, लेकिन कम राशन मिलने की बात उन्होंने एक साल बात जनवरी 2019 में साझा की। ई–दस्तक केंद्र के साथियों ने पूछा तो धीरेंद्र ने बताया कि उन्हें तो 15 किलो अनाज ही दिया जाता है। इस पर धीरेंद्र को बताया गया कि वे 20 किलो राशन के हकदार हैं। कम राशन मिलने की उनकी समस्या 30 जनवरी को होने वाली सामाजिक संपरीक्षा में रखी जाएगी। इसमें बड़े अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। उनके सामने मामला जाएगा तो तत्काल हल

निकल आएगा। ई–दस्तक केंद्र की टीम ने धीरेंद्र से कहा कि वे 30 जनवरी को संपरीक्षा सभा में आना न भूलें। वहां, आएं और अपनी समस्या सुनाएं।

बकौल धीरेंद्र, वे 30 जनवरी को संपरीक्षा में पहुंचे और राशन से जुड़ा किस्सा सुना दिया। साथ ही यह भी कहा कि साहब, मुझे तो जानकारी ही नहीं थी कि मेरा परिवार कितने राशन के लिए पात्र है। इसकी जानकारी तो मुझे ई–दस्तक केंद्र के साथियों ने दी। मुझे तो 20 किलो राशन मिलना चाहिए, लेकिन पीडीएस की दुकान से 15 किलो राशन ही दिया जाता है। पात्रता पर्ची भी महज 20 किलो राशन की दी जाती है। इस तरह मेरे परिवार को तीन सदस्यों का राशन कम दिया जा रहा है। बात पात्रता पर्ची की करें तो दो सदस्यों का राशन कम करके दी जा रही है। धीरेंद्र ने ग्राम पंचायत बृजपुर में हुई सामाजिक संपरीक्षा में ई–वालेंटियर सुरेश और बब्बू बाई की मदद से अपनी समस्या रखी। अफसरों ने पूरे मामले की सुनवाई की और समस्या का समाधान करते हुए पूरा 30 किलो अनाज देने की आदेश दिया। अब धीरेंद्र को हर माह पूरा राशन दिया जाता है।

इस पूरे मामले में ई–दस्तक केंद्र ने भी काफी मदद की। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राही और पात्रता से जुड़े दस्तावेज निकाले। इसमें देखा कि हितग्राही धीरेंद्र के पास 20 किलो राशन की पर्ची थी, लेकिन उसे 15 किलो राशन ही दिया जा रहा था। ई–दस्तक केंद्र के साथियों ने वितरण व्यवस्था का ऑनलाइन मिलान किया, जिसमें 20 किलो राशन दिया जाना दर्ज था। जाहिर है, धीरेंद्र के परिवार के नाम के पांच किलो राशन का गबन हर माह किया जा था। इसके अलावा उनके परिवार के दो सदस्यों के नाम भी पात्रता पर्ची में नहीं चढ़ाए गए थे। इस तरह उन्हें भोजन का अधिकार से भी वंचित रखा जा रहा था। उनको यह हक दिलाने में ई–दस्तक केंद्र ने मदद की।

> “राशन कम मिलने की शिकायत की जांच जिला खाद्य अधिकारी सविता ने की थी। शिकायत सही पाए जाने पर उन्होंने सेल्समैन को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद सेल्समैन ने माफी मांगी और राशन भी पूरा देने लगा।”
>
> – धीरेंद्र गोंड

ई–दस्तक केंद्र ने दिलाई खुशी, दिलाया छिना हुआ निवाला

यूं तो आपने कई सरकारी योजनाओं का लाभ अपात्रों को देने की खबरें पढ़ी होंगी। इनकी जांच बैठी तो लाखों अपात्रों का पंजीयन पाया गया। इसके बाद ऐसे नाम हटा दिए गए, लेकिन अफसरों की मिलीभगत और सिस्टम की लापरवाही के कारण सरकारी योजनाओं का बेजा फायदा लेने वाले अभी भी कम नहीं हैं। इनकी वजह से हजारों पात्र व्यक्तियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे मामले भी कम नहीं हैं, जब सरकारी योजनाओं के हकदार लोगों को इनका लाभ लेने के लिए दर–दर भटकना पड़ा है। इन्हें सही सलाह देने, रास्ता दिखाने और मदद की जरूरत होती है। पन्ना जिले के ऐसे ही दो मामलों में डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना की टीम ने ई–प्लेटफार्म के माध्यम से निःशक्तता प्रमाण पत्र बनवाने में मदद की। इससे उनके परिवारों को मदद के साथ खुशी भी मिली।

पहला मामला पन्ना जनपद के सुकवाहा गांव का है। यह गांव पन्ना जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर है। सुकवाहा के 71 झुन्नारे गोंड के दो बेटे हैं, लेकिन दोनों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वे पिछले कुछ सालों से मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। यही वजह है कि उन्हें मजदूरी भी नहीं मिलती और सच कहें तो वे ठीक से मजदूरी कर भी नहीं सकते। ऐसे में बुजुर्ग झुन्नारे के परिवार के सामने रोज–रोटी का भी संकट था। उनके पास पांच एकड़ जमीन है, लेकिन इसमें इतनी फसल नहीं हो पाती की परिवार का गुजारा सालभर हो सके। झुन्नारे के परिवार में उनके 43 वर्षीय बेटे कंछेदी की पत्नी भगवंती और पांच बच्चों के साथ ही 34 वर्षीय दूसरे बेटे कल्लू की पत्नी सुनीता और दो बच्चे भी हैं। भगवंती और

सुनीता घर के कामकाज करने के साथ ही हीरा खदान में मजदूरी भी करती हैं। इससे उन्हें 120 रुपए मिल जाते हैं। ऐसे में झुन्नारे दोनों बेटों के लिए पेंशन की जानकारी लेने ई–दस्तक केंद्र पहुंचे, जहां से उन्हें सही सलाह मिल गई। ई–दस्तक केंद्र की टीम ने झुन्नारे को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला मेडिकल बोर्ड और समग्र पोर्टल पर पेंशन से जुड़ी जानकारी दी। लोक सेवा केंद्र से आवेदन लेने के बारे में बताया। इस पर झुन्नारे में दोनों बेटों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर दिए हैं।

> “दोनों बेटों के दिव्यांग प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। संस्था के लोग पेंशन दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पेंशन का आवेदन भी जमा कर दिया है।”
>
> – झुन्नारे गोंड

ऑनलाइन शिकायत के बाद मिली पात्रता पर्ची

पन्ना जिले की 75 वर्षीय सुतरानी और उनके 37 वर्षीय बेटे सेवाराम का है। बृजपुर पंचायत से तीन किलोमीटर दूर भाटिया टोला के सेवाराम यादव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके टोले में करीब 40 परिवार रहते हैं और सभी भूमिहीन हैं, इसलिए हीरा खदानें में मजदूरी करने जाते हैं। ये तमाम परिवार कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहते हैं, क्योंकि पीएम आवास जैसी योजना भी यहां पहुंचने से पहले दम तोड़ देती है। बहरहाल, सेवाराम की बात करें। सेवाराम और सुतरानी का जीवन मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उन्हें गरीबीरेखा से नीचे के परिवारों को दिया जाने वाला राशन भी नहीं मिल रहा था। बेटे की हालत से दुखी, सुतरानी चिंता और अभाव से दिनोंदिन सूखती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आते, लेकिन झुर्रियों में जाकर कहां समा जाते पता ही नहीं चलता। बस धंसी हुई आंखों का गीलापन देखकर उनकी पीड़ा का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता था।

राशन की पात्रता के लिए उनके पास समग्र आईडी 45356123 था। गरीबी रेखा की सूची में उनका नंबर 33576 भी था। कहने को तो सेवाराम के पास पांच एकड़ असिंचित कृषि भूमि है, लेकिन वे खेती नहीं कर पाते, इसलिए बंटाई पर दे देते हैं। कई बार इसमें बोनी तक नहीं हो पाती। खेती से जो अनाज मिलता है, उससे दो–तीन माह का गुजारा हो पाता है। सुतरानी को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, लेकिन महज 300 रुपए में ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। सेवाराम का मानसिक निःशक्तता प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उन्हें पेंशन भी नहीं मिल रही थी। ऐसे में कई बार उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं रहता था। सुतरानी ने सेवाराम

का प्रमाण पत्र बनवाने के प्रयास किए। वह किसी की सलाह के बाद ई–दस्तक केंद्र पहुंचीं। यहां टीम के साथियों ने उनकी मदद की।

सुतरानी ने ई–दस्तक केंद्र की टीम को बताया कि उनके पास पिछले चार साल से गरीबी रेखा का कार्ड है, लेकिन पात्रता पर्ची नहीं मिल पा रही है। इस वजह से उन्हें पीडीएस का राशन नहीं मिल रहा है। यानी उनकी स्थिति भोजन का अधिकार से भी वंचित होने की बन गई। सुतरानी ने बताया कि उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच से भी कहा कि उन्हें पात्रता पर्ची दिलाई जाए, लेकिन उन्होंने भी महज आश्वासन ही दिया। यह सब सुनने के बाद ई–दस्तक केंद्र के साथियों ने उन्हें सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत करने की सलाह दी। ई–दस्तक केंद्र के साथियों ने सेवाराम और सुतरानी की पैरवी करते हुए पंचायत सचिव श्रीराम कोरी से इस मामले में बात की, तब पता चला कि सेवाराम को पात्रता पर्ची देने की कार्रवाई एक वर्ष पहले की गई थी, लेकिन पोर्टल में तकनीकी खामी के कारण नई पर्ची जारी होना बंद हो गया है। यह राज्य स्तर की समस्या है। इस समस्या से पंचायत के कई परिवार जूझ रहे हैं।

सेवाराम और सुतरानी ने 28 जुलाई 2018 को ई–दस्तक केंद्र पर आकर सीएम हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत 6596234 दर्ज कराई। इसके बाद उन्हें बताया गया कि उनकी समग्र आईडी को लॉगिन कर सत्यापित कर दिया गया है। पोर्टल अपडेशन के बाद अगले माह यानी सितंबर से राशन की पात्रता पर्ची मिल जाएगी। ऐसा हुआ भी और सेवाराम को राशन की पर्ची मिलने लगी। इसके बाद उन्हें भूखो मरने की स्थिति से छुटकारा मिल गया। हालांकि, ई–दस्तक केंद्र के साथियों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए शिकायत दर्ज होने के बाद उसे फॉलो करते रहे। सेवाराम के टोले की बात विस्तार से करें तो यहां दो हैंडपंप हैं। एक सीसी रोड है। प्राइमरी स्कूल में 28 बच्चे दर्ज हैं और सभी स्कूल जाते हैं। यहां दो शिक्षक हैं, जो बच्चे के स्कूल नहीं जाने पर उनके घर जाकर इसका कारण पूछते हैं, इसलिए सभी बच्चे स्कूल आते हैं; यहां एक मिनी आंगनवाड़ी भी है।

ई–दस्तक केंद्र की मदद से मिलने लगा पूरा राशन

यह मामला पन्ना के धनौजा गांव की बेवा बब्बू बाई का है। उनके परिवार में नौ सदस्य हैं। इस हिसाब से उन्हें हर माह 45 किलो राशन मिलना चाहिए, लेकिन पीडीएस की दुकान से उन्हें 35 किलो राशन ही दिया जा रहा था। जाहिर है, दस किलो राशन का गबन किया जा रहा था। बब्बू ने बताया कि उनके गांव में ई–दस्तक केंद्र की टीम बेसलाइन सर्वे कर रही थी, तब उन्होंने यह बात सर्वे टीम को बताई। उन्होंने बताया कि उनके परिवार का भरण–पोषण उनके दो बेटे और वह मिलकर करते हैं।

बब्बू ने बताया की सर्वे टीम को समस्या बताने के बाद उनके मन में इसके समाधान का भरोसा जागा। टीम ने उन्हें बताया कि 30 जनवरी 2019 को ग्राम पंचायत बृजपुर में सामाजिक संपरीक्षा रखी गई है, जिसमें अपनी बात

रखें। इसमें अफसर भी आएंगे। बब्बू ने टीम की सलाह और ई–वालंटियर की मदद से अपनी समस्या सामाजिक संपरीक्षा में रखी। इसके बाद पड़ताल हुई तो पता चला कि पीडीएस की वितरण सूची में उनके नाम से 45 किलो राशन दिया जाना दर्ज है। इस पर बब्बू ने बताया कि उन्हें तो 35 किलो राशन ही मिलता है। तब स्थिति साफ हुई कि उनके हिस्से के 10 किलो राशन का गबन किया जा रहा है। अफसरों ने उनकी समस्या का समाधान कर दिया और बब्बू के परिवार को 45 किलो राशन दिया जाने लगा। इस तरह ई–दस्तक केंद्र की मदद से बब्बू के चेहरे पर खुशी लौटी।

"अगर हमारे गांव में संस्था काम नहीं कर रही होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी है, जहां शिकायतें सुनी जाती हैं।

वहां से समस्या का समाधान होता है। संस्था की मदद से मुझे राशन पर्ची मिली। अब हमें पूरा राशन मिल रहा है। इससे परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाता है। मैं संस्था के मददगार रवैये से बहुत खुश हूं।"

– सुतरानी

"मैं सुतरानी के मामले में पात्रता पर्ची का आवेदन एक साल पहले कर चुका था। लेकिन, राज्यस्तर से पात्रता पर्ची नहीं दी जा रही थी। बाद में संस्था के साथियों ने पहल की तो नतीजा सकारात्मक रहा। सुतरानी को अनाज की पात्रता पर्ची मिल गई। अब उन्हें राशन नियमित मिल रहा है।"

– श्रीराम कोरी, पंचायत सचिव

शिकायत के बाद दोबारा नहीं दिया गया एक्सपायर्ड पोषाहार

आंगनवाड़ियों में वितरित किए जाने वाले पोषण आहार में धांधली के कई किस्से हैं। कई मामलों में तो प्रदेशस्तर पर बड़े गड़बड़झाले सामने आ चुके हैं। इसके बाद ठेके से लेकर प्रक्रिया बदलने तक के कई प्रयास किए गए। विवाद अभी थमा नहीं है। दूसरी ओर निचले स्तर पर देखें तो वितरण व्यवस्था में भी अनदेखी कम नहीं है। इसमें कई कथित जिम्मेदार लोग अपनी ड्यूटी पूरी करने के चक्कर में हितग्राहियों की सेहत से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। ऐसे में हितग्राहियों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जबकि, आंगनवाड़ियों से दिया जाने वाला आहार तो उनके बेहतर पोषण के लिए होता है। ऐसा ही एक मामला पन्ना जिले के धनौजा आंगनवाड़ी केंद्र का है। हालांकि, इस मामले में एक महिला सुनीला गोंड ने ई–दस्तक केंद्र की मदद से अपनी समस्या का समाधान खुद निकाला। इसके बाद उस समस्या से पूरे गांव को मुक्ति मिल गई।

सुनीला गोंड ने बताया कि वे 16 जनवरी 2019 को आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण आहार लेने पहुंचीं। उन्हें खिचड़ी के पैकेट दिए गए। सुनीला ने बताया कि इस पैकेट पर उत्पादन तिथि 07 सितंबर 2018 लिखी हुई थी। साथ ही इसे तीन माह के अंदर उपयोग कर लेने के स्पष्ट निर्देश लिखे थे। इस तरह खिचड़ी के इस पैकेट की उपयोगिता अवधि सात दिसंबर 2018 को समाप्त हो चुकी थी। यानी करीब सवा महीने पुराना पैकेट दिया गया था। यह बात उन्हें तत्काल इसलिए समझ नहीं आई, क्योंकि वे ज्यादा पढ़ी–लिखी नहीं हैं। सुनीला ने बताया कि खिचड़ी एक्सपायर होने की जानकारी उन्हें तब मिली जब उन्होंने ई–दस्तक केंद्र के साथियों को यह पैकेट बताया। ई–दस्तक केंद्र की टीम उनके गांव में सर्वे करने गई

थी। सुनीला ने उन्हें खिचड़ी का पैकेट बताया तो सभी चौक गए। यह एक्सपायर हो चुका था। उन्होंने बताया कि यह मामला 30 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 की संपरीक्षा में रखा जाना चाहिए। इसमें जिला खाद्य अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। उनके सामने यह बात उठाई जाएगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे।

सुनीला गोंड

सुनीला ने बताया कि उन्होंने ई–दस्तक केंद्र की टीम के मार्गदर्शन के मुताबिक यह मामला खाद्य विभाग की संपरीक्षा सभा में रखा, जहां से अफसरों ने आश्वासन दिया कि आज के बाद ऐसी गलती या लापरवाही दोबारा कभी नहीं होगी। अब हितग्राहियों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री की पूरी पड़ताल की जाएगी। इसके बाद ही वितरण किया जाएगा। इतना ही नहीं अफसरों ने एक्सपायर हो चुके खिचड़ी का पैकेट जारी करने के दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। सुनीला ने बताया कि किसी पर कार्रवाई हुई या नहीं, ये तो उन्हें नहीं मालूम, लेकिन अब वे आंगनवाड़ी से मिलने वाले पोषण आहार के पैकेट पढ़–लिखे लोगों को दिखाने के बाद ही इस्तेमाल करती हैं। हालांकि, अब पोषण आहार में वैसी कोई गलती पकड़ में नहीं आई है। साथ ही आंगनवाड़ी के कर्मचारियों के व्यवहार में भी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि संपरीक्षा जैसी सभाएं होते रहना चाहिए, जिसमें सरकारी सिस्टम की खामियों के मामलों को उठाया जा सके। इससे आमजन को फायदा होगा। कर्मचारी लापरवाही नहीं कर सकेंगे।

30 वर्षीय सुनीला गोंड के परिवार में उनके 33 वर्षीय पति राकेश गोंड और तीन बच्चे हैं। उनका परिवार भटिया टोला में कच्चे मकान में रहता है। सुनीला और राकेश दोनों मजदूरी करते हैं। उन्हें डिजिटल तकनीक की जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुनीला ने बताया कि उनके गांव के कुछ युवा ई–दस्तक केंद्र से जुड़े हुए हैं। सुनीला इन युवाओं की मदद से अपने जरूरत की जानकारी ले लेती इससे गांव के अन्य लोगों की समझ भी विकसित हुई है। अब गांव में कोई भी समस्या होती है तो वे दुर्गेश, आनंद, अमसिया, पूजा, गनेश, सुरेश, नवीन और संत में से किसी से भी बात करके उसका समाधान निकाल लेते हैं। ये युवक–युवतियां अपने स्मार्टफोन पर इंटरनेट के जरिए तमाम जानकारी सर्च कर उन्हें उपलब्ध करा देते हैं। सुनीला और राकेश ने बताया कि ई–प्लेटफार्म और ई–दस्तक केंद्र उनके गांव के लिए वरदान साबित हुआ है।

दशरथ ने सीएम हेल्पलाइन पर की शिकायत तब सुधरा हैंडपंप

सरकारी सिस्टम की अनदेखी के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। जिसे जो काम करना चाहिए, वह पहले तो उसे टालता है और कई बार करता ही नहीं है। कभी काम कर भी दिया तो जनता पर एहसान जताने से नहीं चूकता। ऐसे किस्से आपके आसपास भी होंगे, लेकिन इनका समाधान करने का जो स्मार्ट तरीका दशरथ भामर ने अपनाया, उसने पूरे गांव को खुशियां बांटीं।

दशरथ का परिवार झाबुआ जिले के पेटलावद ब्लॉक की ग्राम पंचायत देवली के झरनिया फलिया में रहता है। यहां के 70 परिवारों की पानी से जुड़ी तमाम जरूरतों के लिए एक हैंडपंप है, जो बंद था और मैकेनिक भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। गांव के लोगों ने सरपंच और सचिव से शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। फिर दशरथ ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर समाधान निकाला। इसमें ई–दस्तक केंद्र ने उनकी मदद की।

चूंकि, सभी 70 परिवारों की हालात एक जैसी है, इसलिए ज्यादातर लोग इधर–उधर की चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मसलन, गांव में कोई समस्या है तो लंबी टिक सकती है, क्योंकि लोगों के पास सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने का वक्त नहीं है। यदि वे सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने लगें मजदूरी कौन करेगा। हां, वे ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और सचिव से जरूर गुहार लगा लेते हैं, लेकिन समाधान यहां से भी नहीं होता।

दशरथ ने बताया सरपंच और सचिव दोनों इनकी मांगों और समस्याओं पर

ध्यान नहीं देते। उनके झरनिया फलिया का हैंडपंप बिगड़ा तो उसे सुधरवाने के लिए सरपंच और सचिव से कई बार गुहार लगाई, लेकिन वे अनसुना करते रहे। दशरथ को रहा नहीं गया और उन्होंने पूरा किस्सा डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के साथियों को सुनाया। उन्होंने अंत में पूछा कि जब अपना चुना हुआ सरपंच भी ध्यान न दे तो क्या करें? इस पर संस्था के समन्वयक सुरेंद्र ने दशरथ को नेक सलाह दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर कॉल करें, जहां से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। दशरथ ने सुरेंद्र की सलाह पर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी, इसके अगले ही दिन हैंडपंप सुधार दिया गया। वहीं, मैकेनिक ने दशरथ को कॉल करके कहा कि आगे कभी हैंडपंप खराब होता है तो उन्हें तत्काल कॉल करें। वे आकर सुधार जाएंगे। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत मत करना। इसके बाद दशरथ के एक फोन कॉल से पूरे झरनिया फलिया को पानी मिलने लगा। लोगों की खुशी देखकर दशरथ का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वे गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान कराने में मदद करते हैं, जो ऑनलाइन शिकायत करने से हो सकता है। अब गांव के लोग भी उनके पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। मददगार व्यक्ति की छवि बनने के बाद से दशरथ को पूरे गांव में सम्मान की नजर से देखा जाता है।

झरनिया फलिया में अनुसूचित जाति के ये सभी 70 परिवार कच्चे मकानों में रहते हैं। चूंकि देवली झरनिया फलिया पेटलावद से करीब 24 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहां रोजगार के साधन नहीं हैं। यहां छोटी जोत की खेती है, लेकिन इसमें परिवार चलाने के लिए पर्याप्त फसल नहीं हो पाती, इसलिए ग्रामीणों को मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ता है। जाहिर है, परिवार पलायन करेगा तो बच्चों को भी साथ जाना पड़ेगा, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। यही वजह है कि यहां पढ़े–लिखे लोग कम हैं। हालांकि, गांव के ज्यादातर लोग पहले अपने खेतों में फसल लगा लेते हैं। इसके बाद मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार दशरथ भामर का है। दशरथ डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के तहत ई–वालेंटियर भी हैं।

> **“हैंडपंप चार माह से बंद था। सरपंच–सचिव से शिकायत की। लेकिन, कोई समाधान नहीं निकला। हमें यह जानकारी नहीं थी कि इसके बाद शिकायत कहां करें।**
>
> **एक दिन ई–वालेंटियर दशरथ की मदद से सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। इस पर अगले दिन मैकेनिक आया और हैंडपंप सुधार गया।”**
>
> **– शांति डिंडौर**

गांव की स्थिति और खेती के हाल देखकर यहां के परिवारों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। दशरथ के परिवार की स्थिति भी बहुत खराब है। इस पर उनके परिवार में सात सदस्य हैं। इनमें पत्नी, दो बच्चे, माता–पिता और छोटा भाई शामिल है। दशरथ के पिता रामा भामर के पास चार बीघा जमीन है, जिसमें परिवार के सभी लोग मेहनत करते हैं। इसके बावजूद इस जमीन में इतना अनाज हो पाता है कि परिवार के खाने का इंतजाम हो जाए, लेकिन बाकी जरूरतों के लिए तो मजदूरी ही विकल्प है। और, मजदूरी करने के लिए पलायन करना पहली और अनिवार्य शर्त है।

"हम एक किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर थे। हमारा ज्यादातर समय तो पानी लाने में ही गुजर जाता था। दशरथ की मदद से ऑनलाइन शिकायत की तो हैंडपंप सुधर गया। अब हमें किसी भी तरह की समस्या होती है तो दशरथ से मदद लेते हैं।"

– कालीबाई

ऑनलाइन शिकायत से डरे सचिव, गंगा को दिलाई पेंशन

कभी आंगनवाड़ी सहायिका रही गंगाबाई ने अपने समय कई लोगों की मदद की। महिलाओं और बच्चों के हक में खूब काम किया। उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का जरिया बनीं, लेकिन 2015–16 में कार्यकाल खत्म हो गया तो उनके लिए पेंशन की व्यवस्था भी नहीं थी। अब उनके सामने रोज–रोटी का भी संकट खड़ा हो गया। एक समय ऐसा आया जब गंगाबाई खुद दूसरों की मदद पर निर्भर हो गई। क्योंकि सरकारी सिस्टम अपने ढर्रे पर काम करे तो किसी को नहीं बख्शता। ऐसा ही गंगाबाई के साथ हो रहा था, लेकिन उन्हें सरकार सिस्टम की नाफरमानी से बचाने की राह डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के साथियों ने निकाल दी।

खंडवा जिले के डाभिया गांव की इस गंगाबाई का किस्सा बड़ा रोचक और सबक सिखाने वाला है। डाभिया में करीब 500 परिवार रहते हैं। गंगा का एक बेटा है, जिसके दो बच्चे भी हैं। बेटा खेती करता है, लेकिन इसमें इतनी फसल नहीं हो पाती कि परिवार का सालभर भरण'–पोषण किया जा सके। जैसे–तैसे करके खाने भर का अनाज हो पाता है। दूसरे जरूरी काम के लिए आय का कोई साधन नहीं था। गंगा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन किया तो ग्राम पंचायत ने उसे निरस्त कर दिया। साथ ही यह भी कहा गया कि वे उम्र के हिसाब से इस दायरे में नहीं आती हैं। हालांकि, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार गंगा की उम्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता के दायरे में आती थी। इसके बावजूद गंगा को पेंशन लेने के लिए दो साल तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन नतीजा सिफर रहा।

गंगाबाई ने बताया कि उनकी समस्या का समाधान डिजिटल डेमोक्रेसी

परियोजना की टीम के सर्वे से हुआ। उनके गांव डाभिया में ई–दस्तक केंद्र की टीम सर्वे कर रही थी, तभी उन्होंने अपनी समस्या उनसे साझा की। टीम के साथियों ने बताया कि तमाम ऑनलाइन सेवाएं आप जैसे लोगों की सेवा करने के लिए चल रही हैं। आप अपने मोबाइल फोन के जरिए भी शिकायत कर सकती हैं। गंगा ने टीम के साथियों से पूरी प्रक्रिया समझी और सीएम हेल्पलाइन 181 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा दी।

गंगा की एक शिकायत से पंचायत स्तर पर हड़कंप मच गया। जो पंचायत सचिव बार–बार मनुहार के बाद भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वह अलसुबह दौड़ा–दौड़ा गंगा के घर पहुंच गया। अब उलटा वही मनुहार करने लगा। जैसा गंगा ने बताया कि सचिव ने कहा– आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं थी। मैं तो आपकी पेंशन का फॉर्म जमा ही करने वाला था। आप अपनी शिकायत वापस ले लो। इस पर गंगा को एक बात तो साफ हो गई कि सचिव का बदला हुआ रूप सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने का परिणाम है। गंगा ने इसी के साथ यह भी ठान लिया कि जब तक पेंशन मिलना शुरू नहीं हो जाता, तब कि वे अपनी शिकायत वापस नहीं लेंगी। उन्होंने अपने निश्चय से सचिव को भी परिचित करा दिया। सचिव से दो टूक कहा– पेंशन शुरू होने तक शिकायत वापस नहीं लेंगी। इस पर सचिव ने उसी दिन गंगाबाई का फॉर्म भरा और अगले दिन आकर कहा कि उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण फॉर्म जमा नहीं हुआ है। गंगा ने यह पूरा माजरा ब्लॉक समन्वयक रामशंकर को सुनाया।

रामशंकर ने गंगाबाई के मामले को लेकर खालवा जनपद पंचायत में बात की। यहां से मिली सलाह के अनुसार उन्होंने पंचनामा बनवाकर सचिव को दे दिया। इसके बाद गंगाबाई का फॉर्म जमा हो गया। जनवरी 2018 से गंगाबाई को पेंशन मिलने लगी। इसकी जानकारी पंचायत सचिव ने गंगाबाई के घर आकर दी। साथ ही यह भी कहा कि वे बैंक जाएं और पेंशन के रुपए निकाल लाएं। लेकिन समस्या यह थी कि सचिव ने गंगाबाई की पासबुक गुमा दी थी। बैंक नई पासबुक नहीं दे रहा था। गंगा पेंशन लेने बैंक पहुंचीं तो अफसरों ने लौटा दिया। इसके बाद रामशंकर ने एक बार फिर गंगाबाई की मदद की। वे बैंक पहुंचे और मैनेजर से बात की। रामशंकर की बातचीत से संतुष्ट बैंक मैनेजर ने गंगाबाई की नई पासबुक बना दी। तब उन्हें पेंशन मिलना शुरू हुआ। गंगा को तीन माह की पेंशन के 1500 रुपए एक साथ जिले, मिले, जिससे वह बेहद खुश हुई।

पांच साल से अंधेरे में था गांव, बिच्छू ने छीन ली थी मासूम की जिंदगी

सरकारी सिस्टम की अनदेखी की सजा कक्षा दूसरी के छात्र अखिलेश ने 17 जून 2017 को मौत के रूप में भुगती। उनके गांव रखेल टोला में 2013 से बिजली नहीं थी। ट्रांसफार्मर जला तो सैकड़ों शिकायतों के बाद भी बिजली विभाग ने बदला नहीं। अखिलेश का गांव पन्ना जिले की ग्राम पंचायत बृजपुर में आता है। यहां करीब 40 परिवारों में 200 से अधिक की आबादी शाम होते ही घरों में कैद हो जाती थी। अंधेरा होने पर सांप–बिच्छू सहित अन्य जहरीले कीड़े–मकौड़ों के काटने का भय रहता था। हालांकि, घरों को रोशन करने के लिए चिमनी थी। लेकिन राशन दुकान से इतना केरोसिन नहीं मिल पाता था कि उसे भी देर तक और पूरे महीने जलाया जा सके। इससे लोगों की दिनचर्या के साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। इन तमाम परेशानियों पर भारी था अखिलेश का हमेशा के लिए चला जाना। उसे बिच्छू ने काटा तो जहर से मौत ही हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोरकर रख दिया। सभी गमगीन, लेकिन गुस्से से भरे हुए लोगों ने तय किया कि अब किसी भी कीमत पर ट्रांसफार्मर बदलवाकर ही रहेंगे। ग्रामीणों को यह नहीं मालूम था कि बिजली विभाग के अलावा शिकायत और कहा करें। बिजली विभाग तो शिकायत करने पर 5000 रुपए का बकाया और निकाल रहा था, जिससे ग्रामीण पहले ही परेशान थे।

एकजुट ग्रामीणों ने पीएलए बैठक में ट्रांसफार्मर बदलवाने की रणनीति बनाई। इसके लिए डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना की टीम से संपर्क किया। साथ ही यह भी कहा कि ट्रांसफार्मर बदलवाने में उनकी मदद करें। दरअसल, रखेल टोला के कुछ लोगों के पास कृषि भूमि है। बाकी

परिवार मजदूरी पर निर्भर हैं, इसलिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने का समय किसी के पास नहीं है। यदि वे ऐसा करने लगें तो मजदूरी का नुकसान हो जाता है। हालांकि, सच तो यह भी है कि इन खेतीहर मजदूरों को पूरे महीने काम भी नहीं मिलता है। दूसरा यह कि पन्ना तक उनकी पहुंच भी नहीं है। ऐसे में करीब पांच साल से सभी परिवार चिमनी की रोशनी में जी रहे थे।

> "मेरे दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन, पांच साल से गांव में बिजली नहीं होने के कारण वे घर में ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। अंधेरे के कारण रात में खाना खाकर सभी सो जाते थे। बिजली नहीं होने से घर के कई कार्यों में दिक्कत आती थी।
>
> संस्था के साथियों की मदद से गांव में बिजली आई। इससे बच्चों के भविष्य में उजियारे की उम्मीद जागी है। हम सभी घरेलू कार्य भी आसानी से कर लेते हैं।"
>
> – पूंजा भाई

रखेल टोला की कोमल बाई और जन्नत बाई ने बताया कि ग्रामीणों ने संपर्क किया तो ई–दस्तक केंद्र के साथियों ने पीएलए बैठक रखी। इस बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि उनके यहां करीब पांच साल से बिजली नहीं है। इसकी तमाम वजह और अब तक की जा चुकी शिकायतों से भी अवगत कराया। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले दिनों बिच्छू के काटने से एक बच्चे की मौत के बाद सभी भयंकर डरे हुए हैं और ट्रांसफार्मर बदलवाने का ठाना है। लेकिन बिजली विभाग के अलावा और कहां शिकायत करें, यह किसी को नहीं मालूम। यह सुनकर ई–दस्तक केंद्र के साथियों ने उनसे समस्या के समाधान के विकल्प की सूची तैयार कराई। इसमें सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत करना और कलेक्टर की जनसुनवाई में मामला उठाना तय किया गया।

ई–दस्तक केंद्र के साथियों ने ग्रामीणों को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने और कलेक्टर की जनसुनवाई में मामला उठाने की प्रक्रिया बताई। उन्हें आवेदन करने की प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि वे मामले को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर सकते हैं। इसे लेकर ट्वीट करें, फेसबुक पर पोस्ट करें और वाट्सएप पर भी मैसेज व वीडियो भेजें। रखेल टोला के महेंद्र गोंड ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी। फिर डिजिटल डेमोक्रेसी के साथियों ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ग्रामीणों की समस्या साझा की। देखते ही देखते यह मुद्दा तमाम जिम्मेदारों तक फैल गया। इस तरह डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के साथियों ने उनकी एडवोकेसी की। अखबारों ने ग्रामीणों की पीड़ा को समझा और लगातार

खबरें प्रकाशित कीं। कोमल ने बताया कि ग्रामीण 30 अप्रेल 2018 को कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे और शिकायती आवेदन दे दिया। इसके बाद कलेक्टर ने ट्रांसफार्मर बदलने के आदेश दे दिए। इस तरह गांव की पांच साल पुरानी समस्या का समाधान हुआ। बिजली विभाग ने 20 जून 2018 को रखेल टोल में नया ट्रांसफार्मर लगा दिया। ग्रामीणों को डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के जरिए अपनी समस्या का समाधान मिला तो वे अब अपनी हर समस्या के लिए पीएलए बैठक करते हैं, जिसमें उनके समाधान के विकल्पों पर चर्चा होती है। इसमें ई–दस्तक केंद्र लगातार मदद कर रहा है।

> “मेरे दो बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में बिजली नहीं होने के कारण वे रात में पढ़ नहीं पाते थे। इसका सीधा असर उनके परीक्षा परिणाम पर होता था। इसके अलावा हमें खाना बनाने सहित अन्य कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। संस्था की मदद से हमारे गांव में बिजली आ गई। संस्था ने पूरे गांव को खुशी दी है।”
>
> – गुड्डी गोंड

ई–दस्तक केंद्र ने साफ किया बुजुर्ग की पेंशन का रास्ता

झाबुआ के ग्रामीणों को परिवार के भरण–पोषण के लिए मजदूरी करने गुजरात जाना पड़ता है। चंद अपवादों को छोड़ दें तो पलायन का किस्सा हर परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। घर छोड़कर मजदूरी के लिए दूर जाना कोई चाहता नहीं है। लेकिन कमजोर माली हालत उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। उस पर भी यदि कोई वृद्ध हो तो जीवन और दूभर सा हो जाता है। यह बुढ़ापा और अधिक भारी तब हो जाता है, जब जवान बेटे–बहू साथ छोड़ दें। झाबुआ के गांव देवली में रहने वाले भमर सोलंकी का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है।

कहने तो भमर का भरा–पूरा परिवार है। चार बेटे हैं। चारों की शादी भी हो चुकी है। लेकिन इनमें से तीन अलग रहने लगे हैं। यूं कहिए कि भमर उनके छोटे बेटे राजू के हिस्से में आ गए। राजू की माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उनके साथ रह रहे भमर को बुढ़ापे में भी मजदूरी करना पड़ता है। यदि चारों बेटे साथ देते तो शायद भमर को मजदूरी से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब भमर, राजू और राजू की पत्नी मजदूरी करने गुजरात जाते हैं। वहां दो–तीन माह काम करते हैं। उनके पास चार बीघा कृषि भूमि भी है। खेती की उपज और मजदूरी से मिलने वाले रुपए मिलाकर तीनों की सालाना आय 30 हजार रुपए ही हो पाती है। जाहिर है महंगाई के इस दौर में इतने कम रुपयों में परिवार चलाना मुश्किल है। नतीजन, उन्हें कई बार कर्ज लेना पड़ता है। इन हालात के बीच भमर को वृद्धावस्था पेंशन से उम्मीद थी कि उससे कुछ मदद हो पाएगी। लेकिन वह भी मिल नहीं रही थी।

भमर के दिल में राहत की उम्मीद तब बंधी जब वे विकास संवाद की

डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना की पीएलए बैठक में शामिल हुए। बैठक में तमाम तरह की जानकारी मिली तो उनके लिए उम्मीद की नई किरण जागी। बैठक में शामिल सभी लोगों को टोल फ्री नंबर की जानकारी दी गई। इसी के साथ पेंशन के मसले पर भी चर्चा हुई तो भमर ने अपनी समस्या बयां कर दी। भमर ने बताया कि उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। उन्हें गरीबी रेखा का कूपन भी मिलता है। इसके बावजूद पेंशन नहीं मिलती। भमर की समस्या समझने के बाद डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना की कार्यकर्ता सुनीता ने रोजगार सहायक से जानकारी लेकर फॉर्म भरने की सलाह दी।

भमर ने आवेदन फॉर्म जमा करने पहुंचे। लेकिन रोजगार सहायक ने फॉर्म जमा करने से इनकार कर दिया। इस तरह भमर के हाथ एक बार फिर निराशा आई। जब भमर देवली स्थित ई–दस्तक केंद्र पहुंचे तो यहां फॉर्म जमा नहीं करने की बात साझा की। यह सुनकर ई–दस्तक केंद्र के साथियों ने लोकसेवा केंद्र पेटलावद में आवेदन जमा कराया। यहां से भमर को यह भरोसा भी दिया गया कि उन्हें पेंशन जल्द ही मिलने लगेगी। भमर को ई–दस्तक केंद्र से मिली मदद के बाद उनका भरोसा यहां गहरा हो गया। अब वे सरकारी सिस्टम से परेशान दूसरे लोगों को भी सलाह देते हैं कि ई–दस्तक केंद्र पर जाकर मदद मांगें। वहां जो लोग रहते हैं वे तमाम तरह की मदद निःशुल्क करते हैं। इसके लिए पीएलए बैठक में जाएं और अपनी समस्या शेयर करें।

> “हमारा परिवार गरीबी रेखा में होने के बावजूद पिताजी को पेंशन नहीं मिल रही थी। मुझे पता चला कि देवली में कोई संस्था है जो लोगों की मदद कर रही है। मैं भी वहां गया। यहां ई–दस्तक केंद्र में डिजिटल तकनीक की जानकारी मिली। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए। मुझे यह भी बताया गया कि ई–वालेंटियर बनकर समाज की मदद कर सकता हूं। मैंने अपने पिता को पेंशन नहीं मिलने की बात सुनीता को बताई तो उन्होंने लोक सेवा केंद्र में आवेदन देने की सलाह दी। इसके बाद में अपने पिता को लेकर लोक सेवा केंद्र पेटलावद गया। यहां आवेदन करने के एक माह बाद उन्हें पेशन मिलने लगी।”
>
> – राजू, भामर के बेटे

पूनम ने यू-ट्यूब देखकर शुरू किया स्टार्टअप

आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के छोटे से गांव कुंडली की लड़की यदि यू–ट्यूब देखकर अपना रोजगार शुरू कर दे तो संभवतः सभी को आश्चर्य होगा। इसकी एक वजह यह भी है कि इस गांव में ज्यादातर परिवार मजदूरी करते हैं। छोटी जोत की खेती होती है। यानी इसमें इतनी पैदावार नहीं हो पाती कि सालभर परिवार का गुजारा किया जा सके। जाहिर है, ग्रामीणों को मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ता है। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच चाहकर भी कुछ नया कर पाना आसान नहीं है। लेकिन 12वीं पास 21 वर्षीय पूनम ने इन हालात को धता बताते हुए स्टार्टअप खड़ कर दिया। पूनम ने अपने पति जगदीश बारिया की मदद से खुद का रोजगार शुरू किया तो सभी आश्चर्यचकित थे। पूनम के परिवार में चार सदस्य हैं और इस काम में चारों ने उनका हौसला अफजाई किया। यह सब संभव हुआ ई–दस्तक केंद्र की मदद से। इस सफलता के पीछे का किस्सा खुद पूनम की जुबानी पढ़ते हैं।

पूनम ने बताया कि उन्हें ई–दस्तक केंद्र पर पीएलए बैठक में यू–ट्यूब की जानकारी मिली। उन्हें लगता था कि लोग यू–ट्यूब का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करते हैं। लेकिन ई–दस्तक केंद्र पर पता चला कि यह खुद का कारोबार खड़ा करने में भी सहायक हो सकता है। यू–ट्यूब पर कई सफल कारोबारियों के वीडियोज हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी सुविधा और पूंजी के अनुसार रोजगार शुरू कर सकते हैं। कुछ वीडियोज में तो एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि किसी व्यापार में निवेश करना है तो कितना करें और तरीका क्या होगा। पूनम ने यू–ट्यूब पर राखी बनाने का वीडियो देखा और उनके जीवन में बदलाव ने दस्तक दे दी।

देखा जाए तो पूनम और जगदीश के जीवन में भी चुनौतियां कम नहीं थीं। जगदीश के माता–पिता के पास चार बीघा जमीन है। लेकिन पथरीली होने के कारण फसल नहीं हो पाती है। आर्थिक स्थिति खराब होने के

कारण उनको मजदूरी करना पड़ता है। जैसा कि जाहिर है, झाबुआ के ज्यादातर लोगों को मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ता है तो जगदीश का परिवार भी इससे कैसे बच सकता था। वे गर्मी के मौसम में कहीं बाहर जाकर मजदूरी करते और पढ़ाई भी जारी रखते। ऐसा करते–करते पूनम बीए की पढ़ाई कर रही है। लेकिन इसके लिए कुंडली से करीब 30 किलोमीटर दूर पेटलावद में किराए का कमरा लेकर रहना पड़ता है। उनकी मुलाकात यहीं पर ई–दस्तक केंद्र के साथियों से हुई थी। पूनम ने उन्हें बताया कि परिवार और पढ़ाई का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। रोजगार भी नहीं है। तब ई–दस्तक केंद्र के साथियों ने उनसे कहा कि रोजगार नहीं है तो क्या हुआ, स्मार्टफोन तो है न। इसके बाद उनके गांव कुंडली में पीएलए बैठक रखी गई, जिसमें पूनम ने भागीदारी की।

पूनम ने बैठक में इंटरनेट, फेसबुक, यू–ट्यूब आदि की जानकारी हासिल की। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि इंटरनेट के जरिए सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी भी घर बैठे ली जा सकती है। इनका लाभ ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। यह सब देखने–समझने के बाद पूनम ने अपने स्मार्टफोन पर यू–ट्यूब ऑन किया और कुछ वीडियो सर्च किए। पूनम को राखी बनाने का वीडियो पसंद आ गया, जिसमें कम खर्च में राखी बनाना सिखाया गया था। पूनम ने बैठक से जाने के बाद अपने पति जगदीश को पूरा किस्सा बताया। उन्होंने जगदीश को भी वीडियो दिखाए। फिर दोनों ने राखियों के नए–नए डिजाइन के वीडियोज देखे। दोनों ने राखी का कारोबार शुरू करने का ठान लिया। जैसे–तैसे कुछ व्यवस्था जुटाई और रतलाम से करीब 3000 रुपए का कच्चा माल खरीद लाए। मोबाइल फोन पर वीडियो देखकर कुछ राखियां तैयार की, इसके बाद अलग–अलग जिडाइन की राखियां बना लीं। दोनों ने मिलकर सात दिन तक राखियां बनाईं। इसके बाद गांव–गांव जाकर बेचा। इससे 8000 रुपए की आय हुई। यानी तीन हजार की पूंजी लगाने पर पूनम और जगदीश ने पांच हजार रुपए का लाभ कमाया। इसके बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। राखियों के बाद उन्होंने सिलाई से जुड़े वीडियोज देखे, जिससे पूनम का हौसला बढ़ा तो वह सिलाई सीखने जाने लगी। इस तरह पूनम और जगदीश की जीवन में डिजिटल प्लेटफार्म ने खुशियां भर दीं। उनकी तरक्की को देखकर गांव के कई लोगों ने बात की तो उन्होंने ई–दस्तक केंद्र पर जाने की सलाह दी। पूनम ने गांव वालों को बताया कि ई–दस्तक केंद्र पर जाने से ही उनका भरोसा बढ़ा और वे स्वयं रोजगार करने लगे। अब वे लगातार बैठकों में जाती हैं और तमाम तरह की समस्याएं कार्यकर्ताओं से शेयर करती हैं, ताकि समाधान निकाला जा सके। उनके साथ अब कई और लोग भी ई–दस्तक केंद्र जाने लगे हैं।

> “सिलाई के मामले में मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। मैं ब्लाउज और सलवार सूट सिल लेती हूं। मैंने नवंबर 2019 में सिलाई मशीन खरीदी और पेटलावद में ही रहना शुरू कर दिया। अब मेरे पास सिलाई का बहुत काम आ जाता है। मैं इससे एक हजार रुपए तक कमा लेती हूं।”
>
> – पूनम

भुलिया से छिना जीने का सहारा तो काम आया डिजिटल प्लेटफार्म

उम्र 71 वर्ष से अधिक। नाम भुलिया बाई गोंड। पता रखेल टोला, जिला पन्ना। रखेल टोला पन्ना से करीब 35 किलोमीटर दूर है। उम्र से जाहिर है कि भुलिया से मेहनत मजदूरी नहीं बनती, वह पेंशन पर निर्भर है। हालांकि, यह भी महज 300 रुपए थी, जिससे गुजर–बसर नहीं हो पाता था तो रखेल टोला से करीब 50 किलोमीटर दूर रहने वाली बेटी मदद करती थी। सितंबर 2017 में भुलिया की पेंशन बंद हुई तो मानो जीने का सहारा छिन गया। अब उनके सामने बेटी के यहां जाकर रहने के अलावा कोई विकल्प न रहा। होने को तो भुलिया की दो विधवा बहुएं हैं। उनके बच्चे भी हैं। लेकिन माली हालत ऐसी नहीं कि वे भुलिया की मदद कर सकें। बहुएं हीरा खदान में मजदूरी करती हैं। लेकिन पूरे महीने काम नहीं मिलता। काम मिलता भी है तो मजदूरी महज 120 रुपए हाथ आती है।

बहरहाल, भुलिया की पेंशन पर गौर करें, जो डिजिटल प्लेटफार्म की मदद से उन्हें दोबारा मिलना शुरू हुई। भुलिया ने पेंशन बंद होने की शिकायत सरपंच और पंचायत सचिव से की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। संयोगवश बेसलाइन सर्वे के दौरान भुलिया की मुलाकात डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के साथियों से हो गई। उन्होंने भुलिया की पासबुक, गरीबी रेखा का कार्ड आदि कागजों को देखा। परियोजना के रेवा ने भुलिया को सीएम हेल्पलाइन 181 में शिकायत करने की सलाह दी। इसके बाद जनवरी 2018 में भुलिया की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई गई। इस पर पन्ना जनपद पंचायत सीईओ ने बताया कि भुलिया को तो नियमिति पेंशन दी जा रही है। यह जानकार सभी हैरान रह गए।

टीम के लोगों ने पड़ताल की तो पता चला कि सीईओ ने गलत जानकारी दी थी। उन्होंने तो ग्राम पंचायत देवरीगाढ़ी की मुनिया विश्वकर्मा की पेंशन की जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने समग्र आईडी नंबर भी गलत

दिया था। सीईओ का गलत जानकारी देना और संस्था के लोगों द्वारा उसकी पड़ताल करने का मामला अखबार में प्रकाशित हुआ तो स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। परियोजना के जिला समन्वयक ने कलेक्टर की जनसुनवाई में भी इस मामले की शिकायत कराई। इसका असर ये हुआ कि सीईओ ने पुनः जांच कराई और गलती सुधारी, तब भुलिया को पेंशन मिलना शुरू हुआ। अब भुलिया पूरी तरह अपनी बेटी या बहुओं पर निर्भर नहीं है। भुलिया के केस की जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंची तो अब वे भी अपनी समस्याएं लेकर ई–दस्तक केंद्र आने लगे हैं। वे डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के साथियों से विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेते रहते हैं।

यू-ट्यूब लाया संध्या के जीवन में नया सवेरा

यह किस्सा ई–वालेंटियर संध्या रजक का है। 25 वर्षीय संध्या का परिवार भोपाल की ईश्वर नगर बस्ती में रहता है। उनके दो बच्चे काव्या पहली कक्षा और कृष्णा केजी1 में पढ़ते हैं। संध्या ने स्मार्टफोन के जरिए आजीविका का साधन जुटा लिया। उन्होंने यू–ट्यूब पर सिलाई से जुड़े वीडियोज देखे, जिससे आजीविका की नई राह खुल गई। हालांकि, उनके पूरे परिवार में एक स्मार्टफोन है, वह भी संध्या के पति देवेंद्र के पास। देवेंद्र एक फर्नीचर दुकान में काम करते हैं, इसलिए सुबह नौ बजे जाकर शाम आठ बजे लौटते हैं। जब देवेंद्र घर में रहते हैं तब उनके फोन का इस्तेमाल सिलाई की नई डिजाइन सीखने के लिए संध्या करती हैं। हालांकि, अब वह सिलाई में लागत निकालकर करीब 2000 रुपए महीना मुनाफा कमा रही हैं। उनके हुनर से प्रभावित होकर दूसरी युवतियों और महिलाओं ने भी उनके पास आना शुरू कर दिया। यूं कहिए कि अब संध्या के यहां सिलाई की ऑनलाइन पाठशाला चलने लगी है। प्रेरणास्पद बात यह है कि संध्या ने अपने हुनर को खुद तक सीमित नहीं रखते हुए दूसरों तक पहुंचा। अन्य युवतियों और महिलाओं की आजीविका का साधन खड़ा करने में मददगार बनीं।

विकास संवाद और निवसीड बचपन संस्था के डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के साथ जुड़कर काम कर रहीं संध्या की सफलता की कहानी सभी को प्रभावित करती है। छोटे से इंटरनेट पैक में सिलाई का हुनर निखारने और घर बैठे काम की आजादी ने संध्या को महिलाओं के बीच आइडियल बना दिया। संध्या के यहां ऑनलाइन सिलाई पाठशाला में किशारी, युवती और महिलाएं लगातार जुड़ती गईं। उनके पास प्रेमबाई,

सरस्वती, शिवकुमारी आदि सिलाई सीखने आती रही हैं। अब वे अपने घरों में सिलाई का काम कर रही हैं, जिससे परिवार की आर्थिक मदद कर देती हैं।

डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना से जुड़ी इन महिलाओं को सामुदायिक बैठकों और ई–वालेंटियर के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप वे यू–ट्यूब पर वीडियो देखकर सिलाई सीखने के साथ ही अपने हुनर को निखार रही हैं। इन महिलाओं का मानना है कि यू–ट्यूब पर वीडियो देखकर सिलाई सीखना मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए किसी प्रशिक्षक को फीस भी नहीं देना है। वहीं, कहीं और सिलाई सीखने जाते तो समय भी ज्यादा निकालना पड़ता। यू–ट्यूब पर अपनी सुविधा के हिसाब से समय निकालकर वीडियो देख लेती हैं। वहीं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिए जाने वाले निःशुल्क प्रशिक्षण के बारे में उनकी राय है कि जब तक एक बैच नहीं बनता तब तक प्रशिक्षण शुरू नहीं किया जाता है। इसका कोई प्रशिक्षण केंद्र बस्ती में नहीं है, जिससे उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता।

संध्या ने बताया कि वे जनवरी 2018 में निवसीड से जुड़ीं। इसके बाद सामुदायिक बैठकों सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने लगीं। मार्च 2018 में उनकी बस्ती में ही डिजिटल सूचना संचार संबंधी बैठक रखी गई। इस बैठक में पहुंची संध्या ने सिलाई को आजीविका का साधन बनाने में रुचि दिखाई। उन्होंने यह भी बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व अरेरा कॉलोनी स्थित एक संस्था में सिलाई का छह माही कोर्स करने के लिए प्रवेश लिया था। लेकिन उसकी फीस 400 रुपए महीना थी, इसलिए वे प्रशिक्षण लेने दो माह ही जा सकीं। इसके बाद से उनके मन में यह बात खटकती रहती थी कि काश वे किसी तरह सिलाई का पूरा प्रशिक्षण ले पातीं। इसके बाद संस्था के कार्यकर्ताओं ने संध्या को यू–ट्यूब पर सिलाई, खाना बनाना, मेहंदी की डिजाइन आदि से जुड़े वीडियो सर्च करना सिखाया। बैठक से जाने के बाद संध्या अपने पति के स्मार्टफोन पर इस तरह के वीडियो देखा करती, जिससे उनका हुनर निखरता गया। संध्या के पास की–पैड वाला मोबाइल फोन है, जिससे जरूरत की बातें ही की जा सकती हैं।

संध्या इससे पहले बच्चों की देखभाल करने और घर के काम निपटाने के बाद पुराने कपड़े सिलने बैठ जाती थी। उनके पास मशीन थी। लेकिन कोई विशेष डिजाइन की सिलाई वे कर नहीं पाती थीं। यह समस्या उन्होंने देवेंद्र को बताई तो उन्होंने अपने फोन पर यू–ट्यूब देने की इजाजत दे दी। जब से यू–ट्यूब मिला तब से वे डिजाइनर सिलाई करने लगी हैं। वे यू–ट्यूब पर गूगल वाइस का इस्तेमाल कर जरूरत के वीडियो खोज लेती हैं। इनमें कटिंग, तुरपाई, सिलाई, कढ़ाई, काज–बटन आदि से जुड़ी जानकारी मिल जाती है।

संध्या अब यू–ट्यूब के दम पर घर बैठे सिलाई करती हैं और सिलाई की पाठशाला भी चला रही हैं। उनके सिले हुए ब्लाउज महिलाओं का खूब पसंद आ रहे हैं। वे एक ब्लाउज की सिलाई 120 रुपए लेती हैं, जिससे लागत और मेहनत निकल आए। संध्या पहले पुराने कपड़ों को सिलकर 500–700 रुपए माह कमाती थी, अब 2000 रुपए महीना तक कमा लेती हैं। अब उनकी आंखों में तैर रहा बच्चों की अच्छी पढ़ाई का सपना पूरा

होता दिख रहा है। वे खुद का स्मार्टफोन भी खरीदना चाहती हैं। संध्या–देवेंद्र के परिवार की माली हालत देखी जाए तो उनके पास गरीबीरेखा का कार्ड होना चाहिए। लेकिन वह अभी तब बना नहीं है। हां, देवेंद्र का पंजीयन असंगठित श्रमिकों में जरूर हो चुका है।

"मैं ब्लाउज और सलवार के नए–नए डिजाइन महिलाओं को बताती हूं। मैं भी यू–ट्यूब पर वीडियो देखकर नए डिजाइन सीखती रहती हूं। मैंने संध्या के पास जाकर सिलाई सीखना शुरू किया है। संध्या भी कई डिजाइन सिखाती रहती हैं। अब मैं अपना रोजगार शुरू करना चाहती हूं। क्योंकि, अब मुझे बहुत अच्छी सिलाई आने लगी है।"

– पूजा

"मुझे मोबाइल फोन करना और रिसीव करना ही आता था। संध्या ने बताया कि वे ब्लाउज और सलवार के नए–नए डिजाइन मोबाइल के जरिए सीखती रहती हैं तो मेरी भी सीखने की इच्छा हुई। संध्या के पास सिलाई भी खूब आने लगी थी। मैंने संध्या के पास जाकर सिलाई सीखना शुरू किया। संध्या हमें यू–ट्यूब पर वीडियो दिखाकर सिलाई के नए डिजाइन सिखाती हैं। अब मैं भी मोबाइल पर ऐसे वीडियो देखती रहती हूं।"

– ममता

फिंगर प्रिंट नहीं आए तो भोजन का अधिकार से वंचित हुए दो परिवार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की दुकानों पर राशन फर्जीवाड़ा रोकने के मकसद से सरकार ने हितग्राहियों का फिंगर प्रिंट का मिलान अनिवार्य कर दिया है। यह अच्छी पहल है, क्योंकि इससे गरीबों के हिस्से के राशन में धांधली के मामले कम हुए हैं। पात्र व्यक्तियों को ही अनाज का वितरण किया जा रहा है। लेकिन यह व्यवस्था उन गरीबों के लिए दुखदायी साबित हुई, जिनकी उंगलियां मेहनत–मजदूरी करते–करते घिस गई हैं। बुढ़ापे में भी कई बार ऐसा होता है कि उंगलियां घिस जाने के कारण प्रिंट नहीं आते हैं। भोपाल और पन्ना जिले के ऐसे दो मामले डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के साथियों के सामने आए तो उन्होंने इनका समाधान ऑनलाइन शिकायत से करवा दिया। इसके बाद डिजिटल प्लेटफार्म पर कई लोगों का भरोसा बढ़ा।

पहला मामला भोपाल की बीडीए की मल्टी बी 3/7 में रहने वाली रेखा जाटव के परिवार का है। रेखा के परिवार में पांच सदस्य हैं और पांचों के फिंगर प्रिंट आना बंद हो गए हैं। नतीजन, पीडीएस की नई व्यवस्था में उन्हें राशन देना बंद कर दिया गया। चूंकि, परिवार की माली हालत ठीक नहीं है। क्योंकि, रेखा के पति पुताई का काम करते हैं, जिससे महीने में करीब 6000 रुपए कमा पाते हैं। इतनी कम रकम में पांच सदस्यीय परिवार का खर्च चलाना मुश्किल है। उनके तीन बच्चे भी हैं, जिनकी पढ़ाई का सवाल भी रेखा और उनके पति के सामने मुंह बाए खड़ा रहता है।

बकौल रेखा उनका नाम वर्ष 2006 से गरीबी रेखा की सूची में है। यानी उनके पास अंत्योदय अन्न योजना का कार्ड है। उनके परिवार को हर माह 35 किलो अनाज दिया जाता था। पांच लोगों के महीने भर के भोजन के

लिए यह पर्याप्त था। जुलाई 2018 से फिंगर प्रिंट आना बंद हुआ तो यह राशन मिलना भी बंद हो गया। हालांकि, फिंगर प्रिंट नहीं आने के मामले में हर माह की 25 तारीख के बाद राशन दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन दुकानदार ने रेखा को बताया कि यह नियम खत्म हो चुका है। उसके जवाब से निराश रेखा ने पीडीएस ऑपरेटर से बात की। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में आधार कार्ड और समग्र आईडी पेश कर अपनी समस्या बयां करने की सलाह दी। लेकिन यह बात रेखा को नहीं पची। रेखा ने कहा कि डिजिटल जमाना है तो सभी काम पीडीएस की दुकानों पर ही क्यों नहीं हो जाते। रेखा ने निवसीड की कार्यकर्ता मंजू को अपनी समस्या बताई तो उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत करने की सलाह दी। यह बात रेखा को ठीक लगी। रेखा ने मंजू की सलाह पर सीएम हेल्पलाइन में कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करा दी। इसके बाद सितंबर 2019 से उनके परिवार को राशन मिलने लगा। अब उनके परिवार को पात्रता के अनुसार 35 किलो राशन मिलता है।

समग्र आईडी बदलने से मैच नहीं किए फिंगर प्रिंट

दूसरा मामला पन्ना जिले के धनौजा निवासी 70 वर्षीय रामलाल गोंड का है। उन्हें 300 रुपए प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन भी मिलती है। उनके पास अंत्योदय योजना का राशनकार्ड है। रामलाल का चार सदस्यीय परिवार कच्चे मकान में रहता है। उनके साथ 65 वर्षीय पत्नी दिहाई, बेटा रज्जू और रज्जू की पत्नी भी रहती है। परिवार की गुजर–बसर के लिए रज्जू और उनकी पत्नी हीरा खदान में मजदूरी करते हैं। कई बार अपने यहां काम नहीं मिल पाने के कारण उन्हें पलायन भी करना पड़ता है। सदस्य संख्या के हिसाब से रामलाल को 35 किलो राशन हर माह मिलता था। लेकिन फरवरी 2019 से उन्हें पीडीएस की दुकान से राशन देना बंद कर दिया गया। क्योंकि, रामलाल के फिंगर प्रिंट मैच नहीं हो रहे थे। हालांकि, इस बीच छह माह उन्हें 15 किलो राशन दिया गया। इसके बाद जब परिवार के किसी भी सदस्य के फिंगर प्रिंट मैच नहीं किए तो राशन पूरी तरह बंद कर दिया गया। इस तरह वे भोजन का अधिकार से वंचित हो गए। ऐसे में घर चला पाना मुश्किल हो गया।

रामलाल के बेटे रज्जू ने पूरी समस्या ई–दस्तक केंद्र पर बताई। ई–दस्तक केंद्र की टीम ने उनकी समग्र आईडी का ऑनलाइन मिलान किया तो पता चला की उनकी समग्र आईडी बदल दी गई है। नई समग्र आईडी 23946444 हाथ से एक पर्ची पर लिख दिया गया, जो 15 किलो राशन की थी। जबकि, उनके परिवार को 35 किलो की पात्रता थी। अंत में दुकानदार ने बताया कि समग्र आईडी अमान्य होने के कारण राशन नहीं दिया जा सकता। रामलाल की पत्नी दिहाई गोंड ने बताया कि उन्होंने सरपंच और पंचायत सचिव से कई बार शिकायत की। लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सचिव ने कहा कि यह मामला ग्राम पंचायत का नहीं है। इसके लिए जनपद पंचायत जाना पड़ेगा। ई–दस्तक केंद्र की टीम ने पूरा मामला समझने के बाद सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत

करने की सलाह दी। रज्जू ने कहा कि शिकायत करने से पहले हम सरपंच और सचिव को एक बार जानकारी और देंगे। क्योंकि, उन्होंने कहा था कि कोई भी शिकायत उन्हें जानकारी देने के बाद करें। यहां दिहाई और रज्जू की बात में सरपंच–सचिव को लेकर विरोधाभास रहा। लेकिन अंततः रज्जू ने हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा दी। रज्जू ने बताया कि उन्होंने अपने गांव में ई–दस्तक केंद्र पर बैठक में उन्होंने स्मार्टफोन चलाना सीखा। इसके बाद 1650 रुपए में एक मोबाइल फोन खरीद लिया। रज्जू की मानें तो अब वह गूगल, यू–ट्यूब, फेसबुक और वाट्सएप का इस्तेमाल भी कर लेते हैं।

> “सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद सितंबर 2019 में 35 किलो राशन मिलना शुरू हो गया। इससे परिवार चलाना आसान हो गया है। संस्था के लोगों की मदद से सीएम हेल्पलाइन की जानकारी मिली। इस पर शिकायत की तो समस्या हल हो गई। सच कहूं तो संस्था की मदद से परिवार को भोजन का अधिकार वापस मिला है।”
>
> – रेखा जाटव

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की तब सुधरे हैंडपंप

पन्ना और खंडवा जिले के ये तीन मामले यह साबित करने के लिए काफी हैं कि सरकारी महकमों के काम का ढर्रा सुधरा नहीं है। अपवाद स्वरूप कुछ मामलों को छोड़ दें तो उसे आजमन की समस्या से सीधा सरोकार नहीं है। फिर मामला पेयजल का ही क्यों न हो। हैंडपंप बंद हो जाए तो मैकेनिक सफेद हाथी साबित होते हैं। उन्हें ढूंढना और फिर हैंडपंप सुधरवाना ग्रामीणों के लिए बेहद मुश्किल साबित होता रहा है, लेकिन डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना की टीम ने इसे बेहद आसान कर दिया। इस टीम ने ग्रामीणों को सीएम हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत करना सिखाया। इसके बाद सभी का हौसला बढ़ा और अब वे किसी भी समस्या का समाधान कराने में खुद को सक्षम महसूस करने लगे हैं।

पहला मामला पन्ना जिले की बृजपुर पंचायत के धनौजा गांव का है। यहां की मूल बस्ती में रहने वाले 45 परिवारों की प्यास बुझाने के लिए महज एक हैंडपंप है। यह हैंडपंप भी बस्ती से करीब 200 मीटर दूर स्कूल के पास है। यूं तो धनौजा में 110 परिवार रहते हैं। लेकिन धनौजा तीन टोलों में बंटा है। गांव की आबादी करीब 450 की होगी। पेयजल की समस्या धनौजा बस्ती की थी। फरवरी 2018 में हैंडपंप की चेन टूटने के कारण गांव में पेयजल संकट खड़ा हो गया। सभी लोग करीब एक किलोमीटर दूर स्थित नाले के किनारे वाले कुएं से पानी पीने को मजबूर हो गए। चूंकि कुआं नाले के किनारे है, इसलिए इसका पानी भी गंदा है। लोग इस समस्या से जूझते हुए करीब 15 दिनों तक हैंडपंप मैकेनिक लालू नंदू को बृजपुर के साप्ताहिक बाजार में तलाशते रहे। हैंडपंप मैकेनिक अपनी तरफ से महीनों जांच करने नहीं आता था, इसलिए यदि कोई हैंडपंप खराब हो

जाए तो वह लंबे समय तक खराब ही रहता था। गांव के लोगों ने दो मार्च 2018 को ई–दस्तक केंद्र के साथियों को अपनी समस्या बताई। उन्होंने हैंडपंप मैकेनिक का नंबर भी दुर्गेश गोंड को दिया। दुर्गेश ने गांव वालों को बताया कि उसे फोन करके शिकायत करना चाहिए। यदि वह हैंडपंप नहीं सुधारता है तो इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की जा सकती है। दुर्गेश ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित के लिए इसका समाधान करना जरूरी हो जाता है।

दुर्गेश ने लालू नंदू को फोन करके हैंडपंप सुधारने के लिए कहा। साथ ही यह भी बताया कि हैंडपंप नहीं सुधारा तो गांव के लोग सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराएंगे। इस पर लालू नंदू ने अगले ही दिन हैंडपंप सुधार दिया। सीएम हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत करने की बात पर मैकेनिक अलर्ट हो गया है। अब वह आठ–दस दिनों में हैंडपंप चेक करने आ जाता है।

तीन माह से बंद थे हैंडपंप, ऑनलाइन शिकायत के बाद सुधरे

पन्ना जिले की बृजपुर ग्राम पंचायत के गिरवानी टोला के 110 आदिवासी परिवार सहित करीब 150 परिवारों के लिए दो हैंडपंप और एक बोरवेल है। लेकिन हैंडपंप खराब हुए तो मैकेनिक ने तीन माह तक कोई खबर नहीं ली। बोरवेल की मोटर तो पांच साल से बंद है, इसलिए उसके पानी के उपयोग का सवाल ही नहीं उठता। गिरवानी टोला से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर बाघन नदी है, जिसका पानी पीने के लिए लोग मजबूर थे। इसमें पानी कम था और वह भी प्रदूषित। लेकिन कोई दूसरा जलस्रोत नहीं होने के कारण ग्रामीण इसी का उपयोग कर रहे थे। इसके दुष्परिणाम बच्चों और बूढ़ों को उल्टी–दस्त के रूप में भोग रहे थे। उल्टी–दस्त के कारण बच्चे नियमित स्कूल नहीं जा पा रहे थे। जाहिर है उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। गांव के लोग पेयजल की समस्या की शिकायत सरपंच और सचिव से कई बार कर चुके थे। लेकिन वे हैंडपंप सुधरवा नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने यह समस्या गिरवानी टोला के ई–वालेंटियर ब्रजेंद्र गोंड को बताई।

ब्रजेंद्र ने ब्लॉक समन्वयक विनोद से चर्चा की। इसके बाद धनौजा के ई–वालेंटियर दुर्गेश गोंड से चर्चा की। सभी में एकराय होने के बाद नौ जून 2018 को ई–दस्तक केंद्र पर पीएलए बैठक रखी गई। इसमें सहभागी प्रणाली से गांव की समस्याओं की पहचान और समाधान पर चर्चा की गई। इनमें पेयजल की समस्या सबसे विकराल थी।

विनोद ने गांव वालों को सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत करने की सलाह दी और इसकी प्रोसेस बताई। उनकी सलाह के बाद गिरवानी टोला के कंछेदी ने अपने स्मार्टफोन से 25 जून को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी। इस पर उन्हें शिकायत के निराकरण का समय 15 दिन दिया गया। नतीजा यह निकला कि मैकेनिक एलएव नंदी ने हैंडपंप सुधार दिए। इस तरह डिजिटल प्लेटफार्म की मदद से ग्रामीणों की समस्या का समाधान हुआ। इससे उनका सीएम हेल्पलाइन पर भी विश्वास बढ़ा। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें इससे पहले सीएम हेल्पलाइन नंबर की जानकारी नहीं थी।

नल जल योजना का प्रस्ताव कराया मंजूर

खंडवा जिले के बाराकुंड गांव में कहने को तो सात हैंडपंप हैं। लेकिन पानी केवल दो ही हैंडपंप से आता है। ये भी अप्रेल–मई तक सूख जाते हैं। इसके बाद गांव में भीषण जलसंकट छा जाता है। गांव में करीब 600 आदिवासी परिवार निवास करते हैं। बाराकुंड खालवा ब्लॉक में आता है, जो बैतूल मेन रोड से दो किलोमीटर अंदर बसा है। गांव के लोगों की आय का जरिया खेती और मजदूरी है। हैंडपंप से पानी नहीं मिलता तो लोग करीब दो किलोमीटर दूर कुएं से पानी लेने जाते। यह पानी भी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके उपयोग से वे कई बार बीमार हो चुके हैं। उन्होंने सरपंच और पंचायत सचिव के सामने अपनी समस्या रखी। लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उनकी पानी की समस्या का समाधान ई–दस्तक केंद्र की सलाह के बाद निकला।

गांव के लोगों ने ई–दस्तक केंद्र की मदद से समुदाय की बैठक आयोजित की। इसमें पेयजल संकट के समाधान पर चर्चा की। इस बैठक में ई–दस्तक केंद्र की टीम ने उन्हें सीएम हेल्पलाइन 181 का महत्व बताया। इसके बाद लोगों ने निर्णय किया कि वे विशेष ग्राम सभा में जाएंगे और पेजयल संकट से निपटने के लिए ठहराव प्रस्ताव देंगे। दूसरी बैठक 14 अगस्त 2019 को रखी गई। इसमें समुदाय के लोगों ने जलसंकट से निपटने के लिए प्रस्ताव तैयार किया। साथ ही तय किया कि 15 अगस्त को ग्राम सभा में प्रस्ताव देंगे और विशेष ग्राम सभा में भी सभी जाएंगे। तय योजना के अनुरूप गांव के लोग बैठक में पहुंचे और जल जल योजना की मांग का प्रस्ताव तैयार कर पेश कर दिया। इसके बाद पंयायतकर्मी ने बताया कि ये प्रस्ताव जनपद और जिला पंचायत भेजा आएगा। दोनों जगह से स्वीकृति मिलने के बाद नल जल योजना मंजूर होगी। गांव के लोगों ने उनकी बात सुनकर तय किया कि 15 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करेंगे। ग्रामीणों की पहल के बाद नल–जल योजना का प्रस्ताव जनपद पंचायत तक जा चुका है।

ई–वालंटियर की मदद से मिला भोजन का अधिकार

68 वर्षीय मांगुड़ी बाई के जीवन में दस वर्ष पहले परेशानियां शुरू हो चुकी थीं, जब उनके पति शोभा भाभर की मृत्यु हुई। उम्र के इस पड़ाव में आकर मजदूरी मिलना और कर पाना दोनों मुश्किल थे। हालांकि, उनका गरीबी रेखा का कार्ड है, जिसपर राशन मिलता है। लेकिन, इसके लिए भी रुपए तो चाहिए। यह दास्तां झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील के देवली गांव की उस महिला की है, जिसके दो बेटे और दो बहुएं भी हैं। बेटे काम की तलाश में अकसर गुजरात पलायन कर जाते हैं। ऐसे में मांगुड़ी इधर–उधर से मांगकर जीवन बसर करती थी। कभी–कभार बेटे बहू कुछ रुपए भेज देते, जिससे राशन खरीद लेती। जाहिर है, मांगुड़ी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की हकदार थी। लेकिन अनदेखी के कारण उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही थी। ऐसा नहीं है कि मांगुड़ी ने प्रयास नहीं किए। उसने पति की मृत्यु होने के बाद सरपंच और पंचायत सचिव से कई बार गुहार लगाई कि पेंशन दी जाए। लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब मांगुड़ी न तो वहां से बाहर जा पा रही थी, न ही उसे यह जानकारी थी कि आगे क्या किया जाए।

मांगुड़ी के जीवन में उम्मीद की किरण तब जागी जब डिजिटल डेमोक्रेसी कार्यक्रम की टीम फील्ड विजिट कर रही थी। मांगुड़ी मिली तो उसने दुखी मन से अपनी पूरी कहानी सुना दी। सर्वे के दौरान संस्था की डिजिटल टीम ने उसकी पेंशन के लिए ग्राम पंचायत के सचिव को आवेदन दिया गया, जिसके बाद इनका पेंशन प्रकरण पास होकर जनपद पंचायत गया। कुछ समय बाद मार्च 2018 से मांगुड़ी को पेंशन मिलना शुरू हुआ। अब उन्हें हर माह पेंशन मिल रही है, जिससे वे राशन खरीद लेती हैं। अब वह

किसी से मांगकर पेट नहीं भरती, न ही बेटे–बहू के रुपए भेजने का इंतजार करना पड़ता।

आज मांगुडी बाई पेंशन पाकर खुश है। गांव के अन्य लोगों ने मांगुड़ी का मामला देखा और समझा तो उन्हें भी ई–दस्तक केंद्र और संस्था पर भरोसा हुआ। उनकी जिज्ञासा डिजिटल डेमोक्रेसी कार्यक्रम को जानने की रही। इस पर कई लोग पीएलए बैठक में शामिल हुए। अब वे भी अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। इस तरह शुरुआत में भले ही अकेले मांगुड़ी को फायदा मिला हो, लेकिन उससे अन्य लोगों को भी भरोसा जागा।

एक कॉल करने से मिला राशन

दूसरा मामला भोपाल का है। काम की तलाश में छत्तीसगढ़ से भोपाल आकर बसे सुमन सतनामी के परिवार को पात्रता के बावजूद सस्ता राशन नहीं मिल रहा था। उनका परिवार करीब 20 साल से पीसी नगर बस्ती में रहता है। सुमन के पति राजेंद्र मजदूरी करते हैं। कर्मकार मंडल योजना के तहत इनकी मजदूरी डायरी बनी थी, जिस पर राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम 2013 अनुसार पात्रता पर्ची जारी की गई थी। उन्हें 20 किलो अनाज, शक्कर दी जाती थी। मामला पात्रता पर्ची रिन्यू कराने को लेकर फंस गया, जो डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के साथियों की मदद से सुलझा।

सुमन ने बताया कि राशन दुकानदार ने कहा कि आधार कार्ड और समग्र आईडी लेकर आएं। ये जमा किए तो दुकानदार बोला– खाद्यान्न पर्ची कलेक्ट्रेट से रिन्यू कराएं। दोनों पति–पत्नी को यह पता नहीं था कि पर्ची कहां से रिन्यू होती है, फिर भी एक दिन राजेंद्र कलेक्ट्रेट गए तो पूछताछ की। लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद राशन मिलना बंद हो गया। इस तरह उन्हें दो साल से राशन नहीं मिला।

सुमन सितंबर 2018 में ई–दस्तक केंद्र पर बैठक में पहुंचीं, जहां अपनी समस्या बताई। इसके बाद मंजू माली और सुनीता ने उनके दस्तावेज का अवलोकन कर सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करवाने की सलाह दी। सुमन ने 20 सितंबर को 181 पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसके अगले दिन उनके पास फोन आया और खाद्यान्न विभाग में अपने दस्तावेज दिखाने को कहा। कलेक्ट्रेट में उनके दस्तावेज जांचे गए और अक्टूबर में उनकी पर्ची रिन्यू हो गई। इसके बाद सुमन को सस्ता राशन मिलने लगा। इस तरह डिजिटल प्लेटफार्म भोजन का अधिकार से वंचित परिवार के लिए मददगार साबित हुआ।

सुमन डिजिटल डेमोक्रेसी कार्यक्रम से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना अनुभव आंगनवाड़ी केंद्र की पोषण आहार समिति की बैठक में भी सुनाया। इसी तरह सुमन ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए भी इस जानकारी का उपयोग किया। उन्हें कनेक्शन नहीं मिल रहा था तो वे गैस एजेंसी पर गईं, जहां जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, तब सुमन ने 181 पर शिकायत दर्ज कराई। सुमन अब सभी तरह की जानकारी लेना चाहती हैं और पढ़ना चाहती हैं। खुद जानकारी प्राप्त कर दूसरों को जागरूक करना चाहती हैं।

डिजिटल डेमोक्रेसी से जागी उम्मीदें, मिली मदद

परिवार की माली हालत खराब होने के बावजूद 64 वर्षीय नारायण डिंडोर को किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। वृद्धावस्था के दौर में परिवार चला पाना उनके लिए दूभर हो चला था। यूं तो परिवार में तीन बेटे और बहुएं हैं। लेकिन उन्होंने नारायण को अलग कर दिया। नारायण पर एक और जिम्मेदारी तब आन पड़ी, जब करीब 10 साल पहले उनकी बेटी मुना का तलाक हो गया। मुना ससुराल से आई और नारायण के साथ रहने लगी। यह दास्तां है झाबुआ की पेटलावद तहसील के आदिवासी बहुल गांव झरनिया के वृद्ध की। गांव में करीब 65 परिवार रहते हैं। कुछ के पास षि भूमि है। ज्यादातर परिवार मजदूरी पर निर्भर हैं। लेकिन गांव में ऐसे संसाधन नहीं कि मजदूरी भी लगातार मिल सके। कृषि भूमि पथरीली होने के कारण मक्का और तुअर की फसल होती है। पैदावार तो भगवान भरोसे ही है। ऐसे में खाने का अनाज सभी को खरीदकर ही लाना पड़ता है।

मुना मजदूरी के लिए राजोद गांव जाती है। जो पैसे मिले उससे अनाज खरीद लेती है। लेकिन इतने कम पैसों में जरूरतें पूरी नहीं होतीं। दोनों के जीवन में नई रोशनी तब आई जब उनका संपर्क विकास संवाद की डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना की टीम से हुआ। देवली के झरनिया फलिया में पीएलए बैठक में ग्रामीणों को पात्रता पर्ची की जानकारी दी गई। उन्हें ई–दस्तक केंद्र के बारे में भी बताया गया। ग्रामीण इससे प्रभावित हुए। एक दिन नारायण ई–दस्तक केंद्र गए और अपनी परेशानी बताई। इसके बाद ब्लॉक समन्वय वालचंद ने देवली के सरपंच से बात की। नारायण से इसके लिए आवेदन करने को कहा।

ब्लॉक समन्वयक ने रोजगार सहायक से बात कर नारायण की समग्र आईडी भी बनवा दी। नारायण की समस्याएं यहां पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उन्हें वृद्धावस्था पेंशन, गरीबी रेखा का राशन कार्ड और शौचालय आदि का लाभ भी नहीं मिला है। इसके लिए ई–दस्तक केंद्र में अपनी बात रखी है। अब डिजिटल माध्यम से नारायण की मदद की जा रही है, ताकि उन्हें इन सुविधाओं का फायदा दिलाया जा सके। नारायण की डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना की टीम से संपर्क में रहते हैं, जिससे उन्हें ये पता चल सके कि उन्होंने जो आवेदन किए हैं उनकी स्थिति क्या है।

इसी तरह एक अन्य मामला झाबुआ जिले के पेटलावद ब्लॉक के जामली गांव का है, जहां राधेश्याम वसुनिया बैंक की लेटलतीफी से तंग आ चुके थे। वसुनिया ने बताया कि वे बार–बार बैंक गए। लेकिन आवेदन और आग्रह के बावजूद एटीएम कार्ड बनाकर नहीं दिया गया। इसके लिए उन्हें जब–तब पेटलावद के चक्कर काटना पड़ता था। वहीं, उन्हें पैसे निकालना हो तो करीब 10 किलोमीटर दूर बैंक जाना पड़ता था। एक दिन देवली गांव में डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के तहत ई–दस्तक केंद्र पर बैठक में शामिल हुए। यहां उन्होंने आपबीती बयां की। यहां केंद्र के सुरेंद्र ने राधेश्याम को सीएम हेल्पलाइन 181 पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। राधेश्याम ने इसकी प्रक्रिया समझी और सीएम हेल्पलाइन पर कॉल कर दिया। राधेश्याम ने बताया कि शिकायत करने के अगले दिन उनके पास बैंक से कॉल आया कि अपना एटीएम कार्ड ले जाएं। इतना ही नहीं, जब राधेश्याम बैंक पहुंचे तो मैनेजर ने कहा कि आपको शिकायत करने के पहले एक बार मुझे बताना करना था। मैं आपको एटीएम कार्ड तुरंत दे देता। बहरहाल, राधेश्याम को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर गहरा भरोसा जागा। इसके बाद से वे स्वयं दूसरों की मदद करने लगे। साथ ही ई–वालेंटियर बनने की इच्छा के साथ ई–दस्तक केंद्र आते–जाते रहते हैं। इस दौरान तमाम तरह की जानकारी हासिल करते हैं, जो अपने गांव के लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। इस तरह राधेश्याम अब समुदाय के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

ई–दस्तक केंद्र ने लौटाई फुंदा और धना की खुशी

खंडवा जिले के डाभिया गांव की फुंदा जब 50 साल की थीं, तब उनके पति मंगल की स्वर्गवास हो गया। इसके बाद फुंदा के सामने जीवन बसर करना किसी चुनौती से कम नहीं था। जैसे–तैसे गुजारा कर रहीं फुंदा को दस साल बाद, यानी 60 की उम्र होने पर पेंशन मिलना शुरू हुआ। इससे उनके खाने का इंतजाम हो जाया करता था। लेकिन, यह खुशी उनके साथ ज्यादा दिन नहीं टिकी और करीब 70 साल की उम्र में पेंशन मिलना बंद हो गया। अब फुंदा के खाने के लाले पड़ने की नौबत आ गई। उन्होंने सरपंच–सचिव के चक्कर लगाए। लेकिन, नतीजा सिफर रहा। इसके बाद उनकी मुलाकात ई–दस्तक केंद्र की टीम से हुई। यहां से फुंदा के जीवन में उम्मीद जाग उठी। उनके साझा प्रयासों से फुंदा को वृद्धावस्था पेंशन मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन, पूरा किस्सा रोचक है क्योंकि जिस उम्र में काम करने की स्थिति भी नहीं रह जाती है, उस उम्र में फुंदा ने पेंशन के लिए काफी प्रयास किए।

फुंदा ने बताया कि उनके गांव डाभिया में 546 परिवार रहते हैं। लेकिन, ई–दस्तक केंद्र से पहले किसी को नहीं मालूम था कि जब सरकारी काम अटक जाएं तो कौन–कौन से माध्यमों से प्रयास कर ये काम कराए जा सकते हैं। उन्हें 60 साल की उम्र में पेंशन मिलना शुरू हुआ, जो दस साल तक मिलती रही। इसके बाद अचानक बंद हुई तो सरपंच और सचिव भी कुछ नहीं कर सके। 2012 में पंचायत में सरपंच और सचिव बदले, उनसे भी गुहार लगाई। एक दिन उनकी मुलाकात ई–दस्तक केंद्र की कार्यकर्ता बबीता और सुनील से हुई। फुंदा ने अपनी पूरी पीड़ा बयां कर दी। उन्होंने कहा कि पेंशन बंद होने से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। सात

माह से पेंशन नहीं मिल रही है। इससे पहले 250 रुपए प्रतिमाह मिल जाते थे। जब सरपंच और सचिव भी मेरी बात नहीं सुनें तो आप ही बताएं मैं क्यां करूं। बबीता और सुनील ने उनकी बात तसल्ली से सुनी और कहा कि पंचायत स्तर पर सुनवाई नहीं हो तो जनपद पंचायत में जाना चाहिए। जनपद पंचायत से इस समस्या का समाधान हो सकता है। वहां सभी भी राहत नहीं मिले तो सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत कर देना चाहिए। फुंदा ने अपनी शिकायत सीधे सीएम हेल्पलाइन में दर्ज करवा दी। इसके बाद उनकी समस्या के समाधान की प्रक्रिया शुरू हुई।

गुहार लगाते-लगाते थक चुकी थीं धना

एक अन्य मामला पन्ना जिले का है। गांव धनौजा की रहने वाली धना बाई गोंड को विधवा पेंशन नहीं मिल रही थी। इसके लिए वे काफी प्रयास कर चुकी थीं। इन प्रयासों में तीन गुजर चुके थे। एक दिन धना ने डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के ई–दस्तक केंद्र पर आयोजित बैठक में अपनी पीड़ा बयां की। यहां ई–वालेंटियर मस्तराम ने धना का राशन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज देखे। धना को ई–दस्तक केंद्र पर उनकी पेंशन से जुड़ी जानकारी दी गई। मस्तराम ने पंचायत की जनसुनवाई में धना का आवेदन ऑनलाइन करवा दिया। कुछ समय बाद धना का विधवास्था पेंशन मिला शुरू हो गया।

इससे पहले धना काफी परेशान थी। कहने को तो उनके पास तीन एकड़ जमीन है। लेकिन, इसमें इतना अनाज नहीं होता कि सालभर का खर्च चल जाए। इससे करीब आठ माह का राशन उपलब्ध हो जाता है। बाकी चार माह के लिए धना को मजदूरी करना पड़ता है। हालांकि, अब पेंशन मिलने लगी है तो कुछ राहत इससे भी मिल गई है। धना ने बताया कि वे ई–दस्तक केंद्र से पहले सरपंच और सचिव से पेंशन दिलाने की मांग कर चुकी थी। लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उनके जीवन में ई–दस्तक केंद्र ने खुशियां लौटा दीं।

> **“मैंने सरपंच और सचिव से कई बार कहा। लेकिन पेंशन नहीं दिलाई जा सकी। इसके बाद मस्तराम से मिली और ई–दस्तक केंद्र गई। उनकी मदद से ऑनलाइन आवेदन किया गया। यह आवेदन मंजूर हुआ और मुझे पेंशन मिलने लगी। इससे मेरी आजीविका में काफी मदद मिली है।”**
>
> **– धनाबाई गोंड**

चार अनाथ बच्चों को मिला जीने का सहारा

मंगी के जीवन में उस वक्त अंधेरा सा छा गया जब जुलाई 2019 में सर्पदंश से उनकी मां छोटी बहू का निधन हो गया। इस हृदयविदारक घटना के बाद 14 वर्षीय मंगी अनाथ हो चुका था। इस अघात से प्रभावित होना वाला मंगी अकेला नहीं था, उनके साथ उनका 10 वर्षीय छोटा भाई छुट्टन भी यह वेदना झेल रहा था। दोनों के जीवन में मुसीबत का अंबार लग गया। जिस ओर देखो उम्मीदें दूर तक नजर नहीं आतीं। क्योंकि, उनके पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। इस घटना को जो भी याद करता, उसके सामने पूरा मंजर तैरने लगता। यह दर्दनाक कहानी पन्ना जिले के धनौजा गांव के बच्चों की है।

ऐसा ही एक और दर्दनाक मामला इसी गांव के ऋषि और ज्योति गोंड का है। ऋषि और ज्योति की मां की मृत्यु भी तीन साल पहले सर्पदंश से हुई थी। इसके बाद दोनों बहुत अकेला महसूस करने लगे थे। मां का साया उठ जाने से दोनों उदास रहते और चिंता में डूबे रहते। जितना हो सकता एक–दूसरे का खयाल भी रखते। क्योंकि, पिता भी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इस गंभीर बीमारी ने जुलाई 2019 में ऋषि और ज्योति सिर से पिता का साया भी छीन लिया। अब ऋषि और ज्योति अनाथ हो चुके थे। उनके सिर से ममता, स्नेह और परवरिश का साया छिन चुका था। इस तरह पन्ना जिले के धनौजा गांव के ये चार बच्चे अनाथ हुए। इनके जीवन में सर्पदंश और गंभीर बीमारी ने मुसीबतों का पहाड़ ला दिया।

मंगी, छुट्टन, ऋषि और ज्योति अब दूसरों पर आश्रित हो चुके थे। उनकी उम्र इतनी भी नहीं थी कि वे काम–धंधा कर सकें। यह तो छोड़िए खेलने और स्कूल जाने की उम्र में भारी मुसीबतों से जूझ रहे इन बच्चों के लिए दो

वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। वे खाने के लिए तरसते थे। स्कूल जाकर पढ़ने और भविष्य गढ़ने का सपना भी उनकी आंखों में था। लेकिन, इनके पूरा होने की आस कम ही दिखती थी। ऐसे में सरकारी सिस्टम ने भी कम दुख नहीं दिए।

मंगी और छुट्टन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जा रहे राशन की पात्रता रखते थे। लेकिन, उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा था। इसकी एक वजह मंगी का अंगूठा नहीं होना भी था। दरअसल, बहुत कम उम्र में मंगी का हाथ जल गया गया था। इससे हाथ बुरी तरह सिकुड़ चुका था। जबकि, आधार कार्ड बनवाने के लिए अंगूठा लगाना जरूरी था। इस पर और बड़ी मुसीबत ये थी कि आधार कार्ड नहीं होने के कारण उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इतना ही नहीं, मंगी की मां की सर्पदंश से मृत्यु होने पर सरकार ने मुआवजा निर्धारित किया था। लेकिन, मंगी को यह मालूम नहीं था कि मुआवजा राशि कैसे मिलेगी। चूंकि मंगी और छुट्टन नाबालिग हैं और आधार कार्ड भी नहीं है, इसलिए बैंक में खाता भी नहीं खुल पा रहा था। इसी तरह की दिक्कतें ऋषि और ज्योति के दरपेश भी थीं।

ई–दस्तक केंद्र ने कैसे की मदद

ई–वालेंटियर रामशरण ने इन चारों बच्चों की दर्द भरी कहानी डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना की टीम को बताई। इसके बाद परियोजना के साथ इन चारों बच्चों के घर गए। उनकी स्थिति को समझा। बच्चों और उनके आसपास के लोगों से बात की। ई–वालेंटियर रामशरण ने चाइल्ड लाइन 1098 पर कॉल किया। उन्होंने चारों बच्चों की परेशानी बताई तो हेल्पलाइन से तीन दिन के भीतर टीम भेजने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी टीम तीन दिन में धनौजा का दौरा करेगी। सभी बच्चों से बात करके हकीकत जानेगी। हुआ भी यही। तीन दिन बाद चाइल्ड लाइन की टीम धनौजा गांव आई और बच्चों के मामले की पड़ताल की। इसके बाद मदद के लिए दो विकल्प दिए। चाइल्ड लाइन की टीम ने कहा कि इन बच्चों को हॉस्टल में रहने की सुविधा मिल जाएगी। वहां रहकर ये पढ़ाई भी कर सकेंगे। दूसरा विकल्प ये है कि यदि गांव के लोग चाहें तो बच्चों के भरण पोषण के लिए उनके बैंक खाते में 2000 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि दी जाएगी।

चाइल्ड लाइन के विकल्प में से चारों बच्चों के परिवारजनों ने उन्हें गांव में ही रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि बच्चे गांव में रहेंगे तो वे देखभाल कर लेंगे। बस, उन्हें सहायता राशि मिल जाए। इससे उनकी पढ़ाई और खाने का खर्च निकल आएगा। इस पर चाइल्ड लाइन की टीम ने कहा कि सहायता राशि बच्चों के 18 साल का होने तक दी जाएगी। यह राशि उनके परिजनों के खाते में जमा की जाएगी। चाइल्ड लाइन ने यह भी शर्त रखी की जो राशि दी जाएगी, वह बच्चों पर ही खर्च करना होगा।

तमाम बातचीत के बाद तय किया गया कि मंगी और छुट्टन की सहायता राशि उनकी बुआ के खाते में जमा की जाएगी। ऋषि और ज्योति की सहायता राशि उनकी दादी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस पर सभी में सहमति बनी। कुछ समय बाद मंगी और छुट्टन को सहायता राशि मिलने लगी। उनकी बुआ के खाते में चार लाख रुपए एकमुश्त जमा किए

गए। यह राशि वे 18 साल की उम्र पूरी करने पर ही निकाल पाएंगे। मंगी के आधार कार्ड का आवेदन भी ऑनलाइन किया जा चुका है। ऋषि और ज्योति को आर्थिक सहायता का मामला भी प्रक्रियाधीन है। जाहिर है मंगी, छुट्टन, ऋषि और ज्योति के जीवन में ई–वालेंटियर रामशरण की पहल से नई रोशनी आ गई।

"बचपन में ही अनाथ हो जाने के कारण इन चारों बच्चों की भूखों मरने की नौबत आ गई थी। ई–वालेंटियर की मदद से मंगी और छुट्टन के खाते में चार लाख रुपए आ चुके हैं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित हो गया। अब ऋषि और ज्योति के पैसे भी संभवतः जल्द आ जाएंगे।"

– सुरेश

"मंगी और छुट्टन को उनकी बुआ किसी तरह पाल रही थी। लेकिन, अब पैसा आ जाने से उनकी पढ़ाई–लिखाई में मदद मिल जाएगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि ऋषि और ज्योति को भी पैसा जल्द मिल जाए।"

– आनंद

ऑनलाइन शिकायत की तो मिली कुएं की राशि

खेती और दूसरों के खेतों में मजदूरी करके परिवार की गुजर–बसर करने वाले कालू भाभर के नाम कपिलधारा योजना में कुआं मंजूर हुआ। इससे उनके परिवार को उम्मीद जागी कि फसलों की सिंचाई होगी तो पैदावार भी ज्यादा हो जाएगी। यह मामला 2018 का है। परिवार का खर्च चलाने में आसानी होगी। मजदूरी के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। इस तरह के कई सपने कालू के परिवार की आंखों में दौड़ने लगे। क्योंकि, उनके गांव देवली में ज्यादातर लोग मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। छोटी जोत की खेती है। उसमें इतनी उपज नहीं हो पाती की सालभर परिवार का खर्च चल सके। कालू के परिवार के सपने उस समय चूर हो गए, जब उनके खेत में कुआं खोदने में लगी सामग्री का पैसा नहीं मिला। हां, मजदूरी जरूर मिल गई थी। हालांकि, डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना के ई–दस्तक केंद्र की पहल से कालू को कुएं के पैसे मिल गए। इससे उनके खेत में कुआं खोदा गया और अब इससे फसलों की सिंचाई भी करते हैं।

42 वर्षीय कालू ने बताया कि उनके गांव 367 परिवार रहते हैं। उनका परिवार हनुमान मंदिर फलिया में रहता है। इसमें ज्यादातर परिवार अनुसूचित जाति के हैं। कहने को तो सभी परिवार खेती पर निर्भर हैं। लेकिन, उपज कम होती है। मजदूरी के लिए पलायन कर जाने के कारण गांव के लोग पढ़े–लिखे भी कम हैं। कुएं की राशि नहीं मिलने पर कालू ने सरपंच और पंचायत सचिव से गुहार लगाई। वे इनके पास चार बार गए। कालू ने बताया कि सचिव ने झूठ बोला कि उनके खाते में सामग्री की राशि जमा हो चुकी है। वे सचिव की बात पर भरोसा करके बैंक जाते और खाली

हाथ लौट आते। दूसरी ओर कालू पर वह दुकानदार पैसे के लिए दबाव बना रहा था, जिसके यहां से उन्होंने कुएं की सामग्री खरीदी थी। परेशान कालू की मुलाकात संस्था के कार्यकर्ता विनोद से हुई। कालू ने विनोद को पूरा किस्सा बताया। इस पर विनोद ने कालू को ई–दस्तक केंद्र पर आने की सलाह दी। विनोद ने कहा कि हमारी समस्या का समाधान पंचायत और ब्लॉक स्तर पर एक माह के अंदर नहीं होता है तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर देना चाहिए।

कालू एक दिन ई–दस्तक केंद्र पहुंचे। यहां टीम को कुएं के पैसे नहीं मिलने की बात बताई। विनोद ने उन्हें सीएम हेल्पलाइन 181 की जानकारी विस्तार से दी। उन्हें भरोसा दिया कि यहां कॉल करने से उनका काम हो जाएगा। इसके बाद कालू ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी। हेल्पलाइन से उनके पर शिकायत नंबर आया। इसके बाद उनके पास एक कॉल भी आया और संबंधित व्यक्ति ने जल्दी ही काम हो जाने का भरोसा दिया। कालू ने कहा कि साहब, जब तक मेरे खाते में पैसे नहीं आ जाते तब तक शिकायत बंद मत करना। कालू ने बताया कि शिकायत करने के करीब पांच दिन बाद मेरे खाते में कुएं की सामग्री के 36000 रुपए आ गए। ये रुपए मैंने उस दुकानदार को दे दिए जिससे सामान खरीदा था। अब मैं कर्ज से मुक्त हो चुका हूं। ई–दस्तक केंद्र की टीम की मदद से मेरे सिर से कर्ज का बोझ उतर गया।

> “ई–दस्तक केंद्र के लोगों की मदद से मुझे कुएं की राशि मिल गई। यदि मुझे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने की जानकारी नहीं मिलती तो न जाने कितने दिन भटकता रहता। दुकानदार भी पैसों के लिए दबाव बना रहा था। अब मैं सभी दबावों से मुक्त हो गया हूं।”
>
> – कालू भाभर, देवली

स्कूल के लिए अब हथेली पर नहीं होगी जान

यूं तो सरकार बच्चों की शिक्षा के कई इंतजाम कर रही है। लेकिन, इनमें कमियां भी बहुत हैं। ज्यादातर मामलों में देखें तो इनकी पूरक जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मसलन, इस ओर कम ही लोगों या कहें कि सिस्टम का ध्यान कम ही जाता है कि बच्चे स्कूल तक कैसे जाएंगे। उनकी स्कूल तक पहुंच सुलभ कराने के प्रयास आज भी नाकाफी हैं। आए दिन ऐसे कई मामले हमारे सामने आते हैं, जिनमें बच्चे जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते हैं। उनके गांव–खेड़ों से स्कूल तक सड़क नहीं है। स्कूल दूसरे गांव में हुआ तो यह दिक्कत और बढ़ जाती है। उस पर भी यदि गांव और स्कूल के बीच नाला या नदी है तब तो जान हथेली पर ही रहती है। बारिश के दिनों में माता–पिता को भी अनहोनी की आशंका खाए जाती है। बच्चे बाढ़ के कारण के कारण कई बार महीनों स्कूल नहीं जा पाते। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होना लाजिमी है। यहां सरकार के बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के तमाम प्रयास विफल हो जाते हैं। ऐसे ही एक मामले से हम इस तरह के तमाम गांवों के बच्चों की पीड़ा को समझ सकते हैं।

पन्ना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर बसे गांव ददोलपुर के बच्चे जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते हैं। इनके गांव ददोलपुर और स्कूल वाले गांव बिक्रमपुर के बीच एक नाला है। दोनों गांवों की दूरी करीब डेढ़ किलोमीटर है। बच्चों को कच्ची सड़क से जाते हुए ये नाला पार करना पड़ता है। यानी सड़क और पुलिया नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में कई बार जान जोखिम में ही रहती है। हालांकि, ददोलपुर में प्राथमिक स्कूल है। लेकिन, इससे आगे माध्यमिक स्कूल के लिए तो बच्चों को यह

नाला पार करना ही पड़ता है। नतीजन, बारिश के दिनों में बच्चे कई बार स्कूल ही नहीं जा पाते। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है।

अब गांव की पूरी आबादी के नजरिए से भी देखें। कभी कोई बीमार हो जाए तो उसे यह नाला पार करना बड़ी चुनौती बन जाता है। मरीजों को नाला पार कराने गोद में बैठाना पड़ता है। या फिर खटिया की डोली बनाकर नाला पार कराना पड़ता है। इससे कई बार समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण अनहोनी हो चुकी है। जाहिर है एक सड़क और पुलिया नहीं होने से पूरा गांव परेशान था। इसके बावजूद शासन–प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं था। इस गांव 750 लोगों की आबादी है। यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार रहते हैं।

गांव ददोलपुर के बाशिंदों की आंखों में सड़क और पुलिया बनने की उम्मीदें उस वक्त तैरीं जब उन्हीं के बीच रहने वाले ई–वालेंटियर आनंद गोंड ने इस समस्या का समाधान निकालने का बीड़ा उठाया। आनंद ने सुरेश और रामशरण के साथ मिलकर सड़क और पुलिया की सदियों पुरानी समस्या से जुड़े वीडियो बनाए। उन्होंने एक व्यवस्थित केस स्टडी तैयार की। इसके बाद ट्विटर अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने ये वीडियो और केस स्टडी मुख्यमंत्री और कलेक्टर तक से साझा किए। एक प्रेस नोट तैयार कर मीडिया को भी अपनी बात बताई। इसकी खबरें की प्रकाशित हुईं। टीवी पर भी समाचार दिखाए गए।

अब तक प्रशासन में हलचल मच चुकी थी। इसके बाद करीब 20 लोगों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में भी इस समस्या को उठाया। नतीजा यह निकला कि कलेक्टर ने सड़क और नाले की पुलिया जल्द से जल्द बनवाने का आश्वासन दिया। ये मामला प्रक्रिया में है। आनंद ने बताया कि इस मामले की शिकायत 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और पन्ना कलेक्टर से की थी। यह पूरा मामला मीडिया से भी साझा किया था, तब पुलिया जल्द ही पुलिया बनाने की बात कही गई थी। लेकिन, इसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। हम इस मामले को फॉलो कर रहे हैं।

अब दादोलपुर में भी बनेगी पुलिया

एक अन्य मामला झाबुआ जिले का है। पेटलावद तहसील के गांव काजबी से जामली जाने वाली अधूरी कांक्रीट सड़क हादसों को न्योता दे रही थी। इससे गांव के सभी 150 आदिवासी परिवार परेशान थे। करीब दो–तीन सौ बच्चे काजबी से जामली स्कूल जाते हैं। फिर गांव के लोगों को कहीं जाना हो तो उन्हें जामली से बस मिलती है। जामली तक इसी खतरनाक अधूरी सड़क से जाना पड़ता है।

दरअसल, ग्रामीणों की मजबूरी है कि जामली जाएं। क्योंकि, माध्यमिक स्कूल, अस्पताल और बाजार आदि जामली में ही है। हादसे की आशंका काजबी के उस नाले पर ज्यादा रहती है, जिसकी पुलिया ठेकेदार ने नहीं बनाई। एक तो खड़े किनारे वाली सीमेंटेड सड़क और फिर पुलिया के नहीं होने से मोटरसाइकिल सवार लोग भी गिरकर घायल हो रहे थे। गांव के लोगों को इन हादसों से निजात दिलाने के लिए ई–वालेंटियर दशरथ भाभर ने मदद की। दशरथ ने रायपुरिया में समाजसेवी संस्था के डिजिटल डेमोक्रेसी परियोजना की जानकारी ली। इसके बाद ई–वालेंटियर बन

गए। दशरथ ने ई–दस्तक केंद्र पर सड़क की समस्या बताई। इसके बाद उन्होंने सड़क के फोटो अपने मोबाइल फोन के जरिए कलेक्टर तक पहुंचाए। उन्होंने ट्वीट कर कलेक्टर को टैग कर दिया। इसके बाद सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा दी। पुलिया बनवाने के लिए दशरथ और ग्रामीणों के साझा प्रयास जारी हैं।

> “इस मामले की शिकायत 29 अगस्त को सीएम हेल्पलाइन और झाबुआ कलेक्टर के यहां की थी। कलेक्टर ने इस शिकायत के आधार पर ठेकेदार पर सख्ती दिखाई। उन्होंने जल्द कार्य करने को कहा। इसके बाद 4 सितंबर को पुलिया का निर्माण कार्य पूरा हो गया।”
>
> – दशरथ भाभर

ISBN 9789381408438